भारतीय वैश्विक
परिषद

दक्षिण कौकसस
में बदलती स्थितियाँ
और
इसके प्रभाव

आईसीडब्ल्यूए संवाद

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली 2024

भारतीय वैश्विक परिषद

दक्षिण कौकसस
में बदलती स्थितियाँ और इसके प्रभाव

आईसीडब्ल्यूए संवाद

भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली 2024

© आईसीडब्ल्यूए 2024

अस्वीकरण: यहाँ व्यक्त किए गए विचार, विश्लेषण और अनुशंसाएं वक्ताओं के व्यक्तिगत हैं।

विषयवस्तु

अवधारणा नोट 5

दक्षिण कौकसस में बदलती स्थितियाँ और इसके प्रभाव

आईसीडब्ल्यूए संवाद 7

कार्यक्रम 65

बायो- प्रोफाइल्स 67

अवधारणा नोट

यूरेशिया का क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है जो क्षेत्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय एवं अंतर- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के स्वरूप को प्रभावित कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण कौकसस यूरोप और एशिया के बीच का एक महत्वपूर्ण संपर्क बिन्दु है, किसी भी क्षेत्र के भू- राजनीतिक या भू- आर्थिक परिदृष्य में परिवर्तन का प्रभाव दक्षिण कौकसस क्षेत्र और उसके बाहर के क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। भले ही क्षेत्र का आकार छोटा है, बड़े अंतरराष्ट्रीय देशों से निकटता और आंतरिक तनाव क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसके प्रभाव को सीमित करते हैं, 2023 की दूसरी छमाही से पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जल्द ही होने वाले हैं। हाल में हुए सैन्य कार्रवाई के बाद अज़रबैजान अलग हुए नागोर्नो- काराबाख क्षेत्र को फिर से अपनी सीमा में शामिल करने की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि आर्मीनिया आर्थिक विकास, क्षेत्र के साथ एकीकरण और पश्चिम से सहयोग की आस में शांति स्थापना को उत्सुक है। एक बड़े घटनाक्रम में, दिसंबर 2023 में, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से शांति बहाल करने एवं संबंधों को सामान्य बनाने के अपनी मंशा की घोषणा की। रूस, ईरान और जॉर्जिया ने भी संवाद प्रक्रिया के क्षेत्रीयकरण को प्रदर्शित करते हुए विकास में योगदान दिया है।

अर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच किस वजह से बदलाव आया है और भविष्य में उनके संबंध कैसे विकसित होंगे, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इस बात का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या बदलाव भारत सहित अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्षेत्र के संबंधों को प्रभावित करने वाला है, जिसका गहरा ऐतिहासिक संबंध होने के अलावा, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूर्वापेक्षाओं एवं अवसरों द्वारा अनिवार्य सभी तीन क्षेत्रीय देशों के साथ मजबूत जुड़ाव है।

भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली दक्षिण कौकसस में वर्तमान स्थितियों, इसके संभावित कार्यप्रणाली, क्षेत्र और उसके बाहर के देशों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों और उचित नीति प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए पैनल चर्चा की मेज़बानी करने का प्रस्ताव देती है।

चर्चा के विषय हैं:

- दक्षिण कौकसस - वैश्विक संदर्भ में रणनीतिक समीक्षा
- दक्षिण कौकसस की बदलती स्थितियों के स्थानीय और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य
- भारत- दक्षिण कौकसस राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहभागिता

मार्च 2024 — भारतीय वैश्विक परिषद

नई दिल्ली — सप्रू हाउस

दक्षिण कौकसस
की बदलती स्थितियाँ
और
इसके प्रभाव

आईसीडब्ल्यूए संवाद

दक्षिण कौकसस

Source: hĩps://.qph.cf2.quoracdn.neĩ/main-qimg-9623e99623b66032c997030f78c92bda

राजदूत विजय ठाकुर सिंह

नमस्कार। भारतीय वैश्विक परिषद, सप्रू हाउस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं राजदूत अचल मल्होत्रा, जिन्होंने इस सत्र की अध्यक्षता करने पर अपनी सहमति दी, को धन्यवाद देती हूँ। राजदूत मल्होत्रा आर्मीनिया में भारत के पूर्व राजदूत थे और शानदार पुस्तक- *साउथ कौकससः ट्रांजिशन फ्रॉम सबजुगेशन टू इंडिपेंडेंस (ट्रेसिंग इंडियाज़ फुटप्रिंट्स)* के लेखक हैं। मैं, *दक्षिण कौकसस में बदलती स्थितियाँ और इसके प्रभाव,* विषय पर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए सहमत होने वाले प्रोफेसर संजय पांडेय, प्रोफेसर अजय पटनायक और प्रोफेसर अख़लाक अहमद का भी स्वागत करना चाहूँगी।

दुनिया इस समय तीन प्रमुख बिन्दुओं पर बहुत ज्यादा उलझी हुई है। पहला है यूक्रेन, दूसरा गाज़ा और तीसरा ताइवान के आस-पास बदलती परिस्थितियाँ। वास्तविकता यह है कि आप आज दक्षिण कौकसस क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं और इसका न केवल इस क्षेत्र के तीन देशों आर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया पर बल्कि क्षेत्रीय एवं भू- राजनीतिक माहौल पर भी प्रभाव पड़ेगा।

दक्षिण कौकसस का लंबा और जटिल इतिहास है और आपने देखा है कि 1990 के दशक में आज़ादी मिलने के बाद से, दक्षिण ओसेतिया और अब्ख़ज़िया को लेकर रूस और जॉर्जिया के बीच युद्ध होते रहे हैं लेकिन नागोर्नो- काराबाख के इलाके को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच भी कई बार युद्ध हुआ है और निश्चित रूप से, आपने बहुत सारे लोगों के मारे जाने के अलावा बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी देखा है। लेकिन सितंबर 2023 में, जब अज़रबैजान ने सैन्य अभियान शुरू किया और नागोर्नो- काराबाख क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, और फिर, मुझे लगता है, आर्मीनिया के बाकी बचे गैर- यहूदी/ गैर- ईसाई लोग भी वहां से पलायन करने लगे।

सितंबर 2023 के बाद, दिसंबर 2023 में एक बैठक हुई जहां दोनों देशों ने शांति की संभावना पर बात की लेकिन स्पष्ट रूप से, वास्तविक स्थिति बहुत खराब बनी हुई थी।

और फरवरी में, आपने देखा कि कुछ सैनिक सीमा पर मारे गए थे। आर्मीनिया के सैनिक सीमा पर मारे गए और इससे एक बार फिर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच खराब संबंध उजागर हुए। आर्मीनिया को लगता है और उसे चिंता है कि अज़रबैजान, शायद सितंबर में अपनी सफलता से उत्साहित होकर, नखचिवन एन्क्लेव के साथ भू-पट्टी (लैंड ब्रिज) बनाने के उद्देश्य से, फिर से आर्मीनिया पर आक्रमण कर सकता है। तो, आर्मीनिया की यही चिंता है।

निश्चित रूप से, अज़रबैजान ने इस बात को ज़ोर दे कर कहा है कि भविष्य में हमला करने की उसकी कोई योजना नहीं है और उन्होंने वास्तव में देश के नेताओं को बदनाम करने का, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और फ्रांस पर, आरोप लगाया है। तो दोनों देशों की यह वर्तमान स्थिति है। लेकिन हाल ही में हुए म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन में इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की बैठक हुई और हम कल से ही देख रहे हैं कि जर्मनी के बर्लिन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी कुछ बातचीत हो रही है।

निश्चित रूप से, मुझे आशा है कि आज पैनल में जिस सवाल पर चर्चा की जाएगी वह होगा - वार्ता में किन मुद्दों को शामिल किया जाएगा? इन मुद्दों के समाधान की क्या संभावनाएं हैं? तो, राजदूत महोदय, मुझे आशा है कि हम उस पर विचार करेंगें। एक और बात है- परंपरागत साझेदारियाँ अब बदल रही हैं और आर्मीनिया, जिसके ईरान और रूस से करीबी संबंध थे, पश्चिम के देशों का रूख कर रहा है। यह यूरेशियन इकॉनमिक यूनियन और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (सीएसटीओ/CSTO) का सदस्य बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि इसने सीएसटीओ (CSTO) की कुछ बैठकों में हिस्सा नहीं लिया और इस बात की अटकलें हैं कि यह सीएसटीओ (CSTO) से बाहर जाने पर विचार कर सकता है क्योंकि यह अब पश्चिम के देशों का रूख कर रहा है। और आप जॉर्जिया के बारे में भी जानते हैं। जॉर्जिया ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू कर दी है।

अब, इन पर पर रूस की नज़र रहेगी। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस इसे कैसे देखेगा? तो, यह एक बड़ा भू- राजनीतिक विकास है जिस पर हमें नज़र रखनी होगी।

और अलग से, निश्चित रूप से, आप अज़रबैजान को भी देख रहे होंगे, वास्तव में जिसके संबंध रूस और ईरान के साथ बहुत अच्छे नहीं थे, आज वह इन्हीं देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना रहा है। तो, ये बदलाव हो रहे हैं और हमें उन पर नज़र रखने की जरूरत है और रूस कैसी प्रतिक्रिया देगा, ईरान की प्रतिक्रिया कैसी होगी। वास्तव में, मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूँगी और कहूँगी मोल्दोवा क्योंकि उसकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी है। और फिर इस क्षेत्र में तुर्की का प्रभाव है। ऐसा कैसे होगा?

तो, ये कुछ व्यापक प्रश्न हैं। भारत का, निश्चित रूप से, इस क्षेत्र के साथ पुराना रिश्ता है और राजदूत अचल मल्होत्रा व्यापक संदर्भ में शायद हमें और अधिक जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यूक्रेन में युद्ध के कारण दक्षिण कौकसस यूरोप और एशिया के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपर्क बिन्दु के रूप में उभरा है और क्योंकि वर्तमान समय में देश एक से अधिक कनेक्टिविटी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, इसलिए यह क्षेत्र वैश्विक कनेक्टिविटी विकल्पों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ और एक बार फिर से पैनल के सभी सदस्यों और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देती हूँ। बहुत- बहुत धन्यवाद।

राजदूत अचल मल्होत्रा

धन्यवाद राजदूत सिंह। साल 2020 में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच हिंसक झड़पों और हाल ही में सितंबर 2023 में, नागोर्नो-काराबाख में अज़रबैजान के सैन्य हमले के कारण दक्षिण कौकसस ने अपनी तरफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रस्तुति में, मैं इस क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण देने, बीते कई दशकों के दौरान इसके विकास का संक्षिप्त इतिहास बताने, 1992 से वैश्विक खिलाड़ियों के बीच इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने की जद्दोजहद, क्षेत्र पर प्रभाव और उनके बढ़ते प्रभाव पर इस क्षेत्र की प्रतिक्रिया को संक्षेप में बताने का प्रस्ताव करता हूँ। मुख्य फोकस क्षेत्रीय संघर्षों और न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि वैश्विक भू- राजनीतिक समीकरणों के लिए उनके निहितार्थ पर होगा। मैं निकट भविष्य में संभावित विकास पर अपने विचार साझा करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, मैं इस क्षेत्र में भारत के पदचिन्हों पर चर्चा करूंगा।

पूर्व सोवियत गणराज्य के तीन और अब स्वतंत्र देश यानि आर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया आधुनिक दक्षिण कौकसस क्षेत्र का निर्माण करते हैं, इन्हें ट्रांस कौकसस (रूस में ज़ाकावकाज़ी) भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में विवादित/अलग हुए क्षेत्र, विशेष रूप से- अबख़ज़िया, दक्षिण ओसेतिया और नागोर्नो-काराब्राख, आते हैं। लगभग 1,86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 1 करोड़ 7 लाख (17 मिलियन) की आबादी वाला दक्षिण कौकसस जातीयता, धर्म और भाषा के मामले में विविधताओं से भरा है। आर्मीनिया के लोग अपोस्टोलिक आर्मीनियाई चर्च के उपासक हैं, जॉर्जिया के लोग जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी हैं और अज़रबैजान मुख्य रूप से एक इस्लामी देश है।

अज़रबैजान तेल और गैस समृद्ध है, आर्मीनिया में तांबे, मोलिब्डेनम, सोने के बड़े भंडार और जिंक, चांदी और यूरेनियम के छोटे भंडार हैं। जॉर्जिया के प्राथमिक घरेलू ऊर्जा संसाधन में जलविद्युत शामिल है और देश ने एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा क्षेत्र विकसित किया है। यहाँ मैंगनीज़, चांदी, सीसा और जस्ता के अयस्कों, कोयला और संगमरमर के भी विशाल भंडार हैं। एकल बाज़ार के रूप में जॉर्जिया यूरोपीय संघ में शामिल होने की राह पर है।

यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से पास है लेकिन सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में गिना जाता है, जहाँ 1991 में आज़ादी के बाद से अलग/विवादित क्षेत्र बार- बार सैन्य संघर्ष कर रहे हैं।

यह क्षेत्र एशिया और यूरोप के चौराहे पर स्थित है एवं उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम के बीच भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसने आज़ादी से पहले और बाद के इतिहास में क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों का ध्यान आकर्षित किया है।

ऐतिहासिक रूप से, मध्ययुग के दौरान, दक्षिण कौकसस क्षेत्र तत्कालीन क्षेत्रीय शक्तियों यानि जारिस्ट रूस, तुर्क साम्राज्य (तुर्की) और फ़ारसी साम्राज्य (ईरान) के बीच जबरदस्त रस्साकशी का विषय था जिन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने के लिए कई युद्ध किए; उनका मुख्य उद्देश्य था

अपने साम्राज्य का विस्तार करना और क्षेत्रीय लाभ प्राप्त करना। प्रथम विश्वयुद्ध और अक्टूबर 1917 की रूस क्रांति के परिणाम ने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। पूरा क्षेत्र धीरे- धीरे विकसित हो रहे यूएसएसआर में शामिल कर लिया गया और एक ओर यूएसएसआर तथा दूसरी ओर तुर्की और ईरान की बीच फिर से सीमाएं खींची गईं।

साल 1991 में यूएसएसआर के विघटन के परिणामस्वरूप आधुनिक दक्षिण कौकसस का उदय हुआ। स्वतंत्र आर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया के इतिहास में पहले पांच वर्ष सबसे अधिक उथल- पुथल वाले रहे, जिसमें हिंसा, गृह युद्ध, तख्तापलट के प्रयास, अंतर- राष्ट्र और अंतर- राजकीय विवादों का बोलबाला रहा और अर्थव्यवस्था का लगभग पतन हो गया। साल 1995 तक, इस क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता की कुछ झलक दिखी।

क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने की होड़ लगभग शुरूआत से ही शुरू हो गई थी। हालाँकि, रूसियों को छोड़ कर, इस बार खिलाड़ी अलग थे, तुर्की और ईरान ने पांव खींच लिए थे। रूसी अब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ प्रतिस्पर्धा में थे। उद्देश्य क्षेत्रीय विस्तारवाद से अलग थे। पश्चिम (यूरोपीय संघ और अमेरिका) के तीन प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य वैचारिक था यानी पूरे क्षेत्र का, राजनीति और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, पश्चिमीकरण करना और क्षेत्र में साम्यवाद के अंत को अपरिवर्तनीय बनाना; दूसरे शब्दों में, वे लोकतंत्र, बाज़ार अर्थव्यवस्था, कानून, जैसे पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे और इस संदर्भ में, वे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक संस्थागत तंत्र विकसित करने में इन सभी देशों की मदद करना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य आर्थिक था, विशेष रूप से अज़रबैजान के कब्ज़े वाले कैस्पियन सागर के प्रचूर ऊर्जा संसाधन। विचार यह था कि ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में निवेश कर और ऊर्जा की कमी वाले यूरोप के लिए अज़रबैजान से ऊर्जा प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए और इस तरह रूस पर निर्भरता को यथासंभव कम किया जाए। तीसरा क्षेत्रीय विवादों के समाधान के संदर्भ में सुरक्षा का आयाम था,

विशेष रूप से नागोर्नो- काराब्राख पर आर्मीनिया- अज़रबैजान युद्ध और जॉर्जिया के अब्रखज़िया और दक्षिण ओसेतिया के अलग हुए क्षेत्रों के साथ विवाद। संघर्षों के समाधान या कम- से- कम प्रभावी प्रबंधन ने अन्य दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया होगा। रूस के लिए, पूर्व सोवियत संघ के सभी देश उसके "निकटस्थ" थे- उसके प्राकृतिक प्रभाव के क्षेत्र थे।

शुरुआती दौर में, तीनों देश यूरोपीय पहचान हासिल करने की ओर झुके दिखे। समय के साथ, उनमें से प्रत्येक ने एक अद्वितीय विदेश नीति प्रक्षेपवक्र विकसित किया। जॉर्जिया यूरो- अटलांटिक संरचनाओं (ईयू और नाटो की सदस्यता) के साथ पूर्ण एकीकरण की अपनी नीति का पालन करना जारी रखे हुए है। अज़रबैजान- स्वरूप में लोकतांत्रिक लेकिन वस्तुतः निरंकुश और शुरुआत से ही एक ही परिवार द्वारा शासित- पश्चिम के साथ किसी भी प्रकार के सामाजिक- राजनीतिक या आर्थिक एकीकरण का विरोध करता है लेकिन आर्थिक सहकारिता और सहयोग के खिलाफ नहीं है। इसका सीधा परिणाम है अज़रबैजान के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अमेरिकी और यूरोपीय निवेश। आर्मीनिया पश्चिम (पसंद से) और रूस (मज़बूरी से) के बीच फंस गया है। आर्मीनिया की अर्थव्यवस्था में रूस की गहरी पैठ है। साथ ही इस देश में सैन्य अड्डे एवं सुरक्षा कर्मियों के कारण रूस की मजबूत सैन्य उपस्थिति भी है जो तुर्की, जिसके साथ आर्मीनिया के संबंध तनावपूर्ण हैं, के साथ आर्मीनिया की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आर्मीनिया रूस के नेतृत्व वाली आर्थिक (यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियनः ईईयू/ EEU) और सुरक्षा (सीएसटीओ/CSTO) व्यवस्थाओं का भी हिस्सा है। रूस में बड़ी संख्या में आर्मीनिया के लोग रहते हैं तो अपने देश के लिए अच्छा खासा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का स्रोत हैं।

संक्षेप में, तीनों वैश्विक खिलाड़ियों में से प्रत्येक ने इस क्षेत्र में कुछ सीमा तक राजनीतिक और आर्थिक पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल की है लेकिन कोई भी वैश्विक खिलाड़ी इस क्षेत्र पर अकेले नियंत्रण करने का दावा नहीं कर सकता है।

एक क्षेत्र जिसमें प्रतिस्पर्धी ताकतों (अमेरिका+ यूरोपीय संघ और रूस) ने शुरू से ही एक साथ काम किया है, वह है क्षेत्रीय विवादों को दूर/प्रबंधित करने के लिए मध्यस्थयता/हस्तक्षेप। हालाँकि, सैन्य संघर्षों (रूस- जॉर्जिया/2008 और आर्मीनिया- अज़रबैजान/ 2020 और 2023) ने इस संदर्भ में वैश्विक शक्तियों की अक्षमता को उजागर किया, जिसने अन्य खिलाड़ियों, विशेष रूप से तुर्की को इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को फिर से सक्रिए करने के लिए प्रेरित किया है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के देशों के बीच वैश्विक शक्तियों के आत्मविश्वास में कुछ कमी आई है। इस विषय पर मैं आगे चल कर विस्तार से चर्चा करूंगा।

यूएसएसआर के गठन के दौरान, घटक सोवियत समाजवादी गणराज्यों के इलाके में एक निश्चित संख्या में स्वायत्त गणराज्य/क्षेत्र (ओब्लास्ट) बनाए गए थे; यह उनकी विशिष्ट जातीय, धार्मिक और भाषाई पहचान की मान्यता में किया गया था। इन क्षेत्रों में से अब्ख़ज़िया और दक्षिण ओसेतिया (जॉर्जिया में) और नागार्नो- काराबाख (अज़रबैजान में) स्वतंत्रता के बाद के भी काफी समय तक सशस्त्र विवाद का स्रोत रहे। तुर्की की सीमा से सटे काला सागर पर जॉर्जिया के भीतर एक और स्वायत्त क्षेत्र अदज़ारा के नेतृत्व में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के दौरान त्बिलिसी में केंद्रीय प्राधिकरण के प्रति बहुत कम सम्मान था। तत्कालीन नवनिर्वाचित जॉर्जियाई राष्ट्रपति साकाशविली ने कुशल कूटनीति और बल प्रयोग की धमकी देकर ऐसी स्थितियां पैदा कर दीं कि अदज़ारा के नेता, असलान अबाशिद्ज़े को 5 मई 2004 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन के बीच रूस के लिए रवाना होना पड़ा। अदज़ारा अब “अदज़ारा स्वायत्त गणराज्य” है जो जॉर्जिया में पड़ता है और उसका ही एक हिस्सा है।

बढ़ते राष्ट्रवाद और 1991 में यूएसएसआर के आसन्न विघटन की पृष्ठभूमि में जॉर्जिया के भीतर स्वायत्त क्षेत्रीय इकाईयों के रूप में बनाए गए अब्ख़ज़िया और दक्षिण ओसेतिया जॉर्जिया से अलग हो गए। इसके परिणामस्वरूप 1994 में संयुक्त राष्ट्र, ओएससीई, यूरोपी संघ की भागीदारी के साथ रूस की मध्यस्थता में युद्धविराम के समझौते के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष रोक दिए गए,

जबकि रूस मुख्य भूमिका में था। समझौतों के बाद अब्रखज़िया और दक्षिण ओसेतिया की राजनीतिक स्थिति के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लंबी वार्ता हुई, जिसने संयोग से जॉर्जिया और एवं अलग हुए क्षेत्रों एवं अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रयासों के बीच चल रहे विवाद के बीच क्रमशः अक्टूबर 1999 और मई 1992 में एकतरफा स्वतंत्रता की घोषणा की। रूस समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय (जिसका समर्थन दोनों क्षेत्रों को प्राप्त था) ने स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी।

साल 2004- 2008 के बीच की अवधि में जॉर्जिया के राष्ट्रपति के यूरो-अटलांटिक संरचनाओं के साथ एकीकृत होने के दृढ़ संकल्प के कारण जॉर्जिया और रूस के बीच संबंधों में कमी देखी गई, अप्रैल 2008 में नाटो की घोषणा कि जॉर्जिया (और यूक्रेन) को नाटो में शामिल किया जाएगा, हालांकि कोई निश्चित समय सीमा का संकेत नहीं दिया गया था। रूस नाटो के पूर्व की ओर अपनी सीमाओं तक विस्तार की संभावना से चिढ़ गया था। इसके अलावा, रूस के विरोध के बावजूद 2008 में कोसोवो की स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणा को मान्यता देने का अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों का निर्णय रूस को पसंद नहीं आया था।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, 2004 में दोषी अदज़ारा पर लगाम लगाने में अपनी सफलता से उत्साहित होकर जॉर्जिया के राष्ट्रपति साकाशविली ने दक्षिण ओसेतिया में कुछ कदम उठाए, जिसेक कारण अंततः रूस और जॉर्जिया के बीच खुल्लम-खुल्ला युद्ध हुआ (7-12 अगस्त 2008) जो यूरोपीय संघ की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा मध्यस्थता के बाद समाप्त हुआ। 15 सितंबर 2008 को एक कार्यान्वयन समझौता किया गया। नतीजों में से एक था- 26 अगस्त 2008 को रूस द्वारा अबखज़िया और दक्षिण ओसेतिया को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना।
रूस के तीन सहयोगी- वेनेजुएला, निकारागुआ और नाउरू द्वीप- ने भी मान्यता देने में रूस के निर्णय का साथ दिया जबकि शेष अंतरराष्ट्रीय समुदाय इससे दूर रहे। अन्य महत्वपूर्ण परिणाम युद्ध के परिणामों और उससे संबंधित मुद्दों को

संबोधित करने के लिए जिनेवा अंतरराष्ट्रीय परिचर्चा (जीआईडी/GID) नाम के एक नए मंच को बनाना था। जीआईडी की सह- अध्यक्षता यूएन, ओएससीई, ईयू के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है जिसमें जॉर्जिया, रूस, अमेरिका के साथ- साथ अब्रखज़िया और दक्षिण ओसेतिया के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। सुरक्षा और मानवीय मुद्दों पर समानांतर रूप से दो कार्य समूहों की बैठकों में चर्चा होती है।

जीआईडी का 59वां दौर 5-6 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। 15 वर्षों से चल रहे विचार- विमर्श के बावजूद कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। कोई भी इसे सुरक्षित रूप से "जमे हुए संघर्ष" के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, जिसके किसी भी समय भड़क जाने की संभावना है।

नागोर्नो- काराब्राख पर अर्मीनिया- अज़रबैजान विवाद की उत्पत्ति जुलाई 1921 में नागोर्नो- काराब्राख (एनके) नामक एक स्वायत्त क्षेत्र के दोषपूर्ण निर्माण में निहित है, जो ऐतिहासिक रूप से यहाँ तत्कालीन विकसित यूएसएसआर में दक्षिण कौकसस के शामिल होने के दौरान मुस्लिम बहुल अज़रबैजान क्षेत्र में एक एन्क्लेव के रूप में मुख्य रूप से ईसाई काराब्राख आर्मीनियाई लोग रहते हैं; इसे इस तरह से किया गया था कि एनके (NK) भौगोलिक रूप से आर्मीनियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य के करीब आ गया लेकिन आर्मीनिया के साथ उसकी सीमाएं साझा नहीं हुई। सत्तर साल बाद, क्षेत्र में बढ़ते राष्ट्रवाद और सोवियत संघ के आसन्न पतन की पृष्ठभूमि में, नागोर्नो- काराब्राख ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप आर्मीनिया और अज़रबैजान के लोगों के बीच पूरे पैमाने पर युद्ध हुआ (1991-94), जिसके परिणामस्वरूप न केवल नागोर्नो- काराब्राख बल्कि अज़रबैजान के सात निकटवर्ती जिले भी आर्मीनिया के नियंत्रण में आ गए। एनके में वास्तविक रूप से चुनी गई सरकार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता नहीं मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस की अध्यक्षता वाले 11- सदस्यीय ओएससीई (OSCE) मिन्स्क समूह ने 25 वर्षों से अधिक समय तक संघर्ष को हल करने के लिए कई प्रयास किए जो निरर्थक साबित हुए, जिसके दौरान समूह मुश्किल से संघर्ष का प्रबंधन कर सका और कई बार वह उस भूमिका में भी विफल रहा।

इस बीच, अज़रबैजान ने अपने पेट्रोडॉलर के बल पर अपनी सैन्य क्षमताएं बनाईं और जाहिर तौर पर अज़रबैजान ने सैन्य माध्यमों से मामले को सुलझाने का फैसला किया।

इस प्रकार दूसरा आर्मीनिया- अज़रबैजान युद्ध 27 सितंबर 2020 को शुरू हुआ और 10 नवंबर 2022 को आर्मीनिया, अज़रबैजान और रूस के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के साथ समाप्त हुआ; इसमें रूस ने मध्यस्थता की थी। इस युद्ध को 44 दिनों का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध और जिन शर्तों पर यह समाप्त हुआ, उनका न केवल आर्मीनिया, नागोर्नो-काराब़ाख और अज़रबैजान पर बल्कि क्षेत्र के भू- राजनीतिक समीकरणों पर भी प्रभाव पड़ा।

- आर्मीनिया गणराज्य और नागोर्नो- काराब़ाख के आर्मीनियाई लोगों के लिए, युद्ध का मतलब अपमानजनक हार था, जिससे वे हमेशा के लिए आहत हो गए। आर्मीनिया के लोगों को न केवल अज़रबैजान के कब्ज़े वाले क्षेत्रों को खाली करने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि नागोर्नो- काराब़ाख के कुछ हिस्सों पर अज़रबैजान के नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए भी मजबूर किया गया। इसके अलावा लाचिन गलियारा, जिसे आर्मीनिया के लोगों ने आर्मीनिया गणराज्य को नागोर्नो- काराब़ाख से जोड़ने के लिए बनाया था, रूस की शांति सेना के अधीन आ गया। आर्मीनिया अपनी ज़मीन से अज़रबैजान और उसके स्वायत्त क्षेत्र नखिचेवन के बीच एक परिवहन लिंक देने पर भी सहमत हुआ, जो भौगोलिक रूप से आर्मीनियाई क्षेत्र द्वारा अज़रबैजान के मुख्यभूमि से अलग किया गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझौता युद्ध के मूल कारण यानी नागोर्नो- काराब़ाख की राजनीतिक स्थिति पर पूरी तरह से चुप था;

- युद्ध ने शक्ति संतुलन को बड़े पैमाने पर अज़रबैजान के पक्ष में कर दिया। यहाँ से आर्मीनिया को कमजोर स्थिति के साथ बातचीत करनी थी;

- युद्ध को रोकने में विफलता वैश्विक मध्यस्थों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के लिए

सम्मान खोने वाली बात थी, जिन्हों या तो कोई प्रयास नहीं किया या केवल आधे- अधूरे मन से प्रयास किया और अपने प्रयासों में असफल रहे;

- रूस वहाँ सफल रहा जहाँ दूसरे असफल हुए, हालांकि मानवीय और भौतिक हानि के रूप में गंभीर क्षति को रोका नहीं जा सका;

- नवंबर 2020 के समझौते के अनुसार, रूस ने युद्ध क्षेत्र में शांति सेना के रूप में 2000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की। रूस के पास पहले से ही आर्मीनिया में एक सैन्य अड्डा है, इसके अलावा तुर्की और ईरान के साथ आर्मीनिया की सीमाओं की रक्षा करने वाले 4500-रूसी सैनिकों की एक सशक्त टुकड़ी भी है। अगस्त 2008 में जॉर्जिया के साथ युद्ध के बाद से रूस ने जॉर्जिया से अलग हुए क्षेत्रों अर्थात् अब्रखज़िया और दक्षिण ओसेतिया में भी अपनी सैन्य उपस्थिति बना ली है। इस प्रकार रूस ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को और मजबूत किया है;

- तुर्की, ओएससीई मिन्स्क ग्रुप का सदस्य होने के बावजूद, अज़रबैजान के साथ तुर्की की निकटता और आर्मीनिया के साथ दुश्मनी को देखते हुए आर्मीनिया द्वारा सख्त आपत्तियों के कारण अतीत में कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सका। हालाँकि, माना जाता है कि 1992-94 के युद्ध में अज़रबैजान द्वारा खोए गए क्षेत्रों को पुनःप्राप्त करने के लिए तुर्की ने अज़रबैजान को सैन्य मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  साल 2020 के युद्ध के दौरान तुर्की ने भी अज़रबैजान को बड़े पैमाने पर नैतिक और भौतिक सहयोग दिया था। इस प्रकार तुर्की को इस क्षेत्र में कुछ भूमिका की अनुमति मिलने की उम्मीद है। हालाँकि, रूस ने तुर्की की एक सीमा से आगे कोई भूमिका नहीं निभाने दी। नवंबर 2020 का समझौता युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में केवल रूस की शांति सेना की उपस्थिति का प्रावधान करता है। हालाँकि, रूस और तुर्की के बीच एक अलग समझौता ज्ञापन के तहत, नवंबर 2020 समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक रूस- तुर्की संयुक्त केंद्र की स्थापना (30 जनवरी 2021) की गई थी;

- आर्मीनिया ने युद्ध के दौरान आर्मीनिया को पर्याप्त सहयोग नहीं देने पर रूस और रूसी नेतृत्व वाली सुरक्षा संरचनाओं के प्रति अपनी

निराशा नहीं छिपाई- एक ऐसा बहाना जिसका इस्तेमाल आर्मीनिया रूस से दूर जाने और किसी और से मदद पाने के लिए कर सकता है;

- अज़रबैजान स्पष्ट रूप से कह रहा था कि मिन्स्क ग्रुप की भूमिका समाप्त हो गई है, विवाद अब नहीं है और काराबाख में आर्मीनियाई लोग अज़ेरी क्षेत्र में मूल आबादी के साथ रह सकते हैं;
- फ्रांस- मिन्स्क ग्रुप के तीन सह- अध्यक्षों में से एक, के साथ अज़रबैजान के संबंध खराब होने लगे क्योंकि अज़रबैजान ने फ्रांस पर अज़रबैजान के खिलाफ और आर्मीनिया के पक्ष में पूर्वाग्रह का आरोप लगाया। दिसंबर 2023 में, अज़रबैजान ने दो फ्रांसीसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।

साल 2020 युद्ध के बाद की जमीनी स्थिति यह थी कि एनके (NK) में वास्तविक सरकार चलती रही। युद्ध से उत्पन्न मानवीय मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इसके साथ ही, आर्मीनिया और अज़रबैजान वैश्विक खिलाड़ियों के संपर्क में थे ताकि उन्हें शांति संधि समाप्त करने और नवंबर 2020 के त्रिपक्षीय समझौते के तहत निर्णयों को लागू करने में मदद मिल सके। रूस के "यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान" ने अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के साथ रूस के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया और उनका प्रयास रूस को मध्यस्थता प्रक्रियाओं से बाहर करना था। आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच शांति संधि पर सहमति नहीं बन पाई।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अज़रबैजान ने 19 सितंबर 2023 को एनके (NK) रक्षा बलों के खिलाफ एक तेज सैन्य आक्रमण आरंभ कर आश्चर्यचकित कर दिया, इसे "आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों" के खिलाफ एक कार्रवाई बताया। रूस ने अपनी चिंता व्यक्त की जबकि अमेरिका और यूरोप ने हमले की निंदा की।

क्षेत्र में तैनात रूस की शांति सेना ने हस्तक्षेप किया और 20 सितंबर को शीघ्र ही युद्धविराम समझौता हो गया। जातीय आर्मीनियाई लोगों के नज़रिए से बहुत कम समय में बहुत अधिक नुकसान हुआ था।

काराबाख आर्मीनियाई लोगों की लगभग पूरी आबादी भाग कर आर्मीनिया की शरण में चली गई जबकि नागोर्नो- काराबाख अज़रबैजान के नियंत्रण में आ गया। नागोर्नो-काराबाख की रक्षा सेनाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया गया और उन्हें भंग कर दिया गया। एनके की वास्तविक सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सत्ता में न रहे का फैसला सुनाया लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और बताया गया है कि उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया है। संक्षेप में, अज़रबैजान के आक्रमण ने जातीय काराबाख आर्मीनियाई लोगों की एक स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षाओं को घातक झटका दिया।

साल 2020 के विपरीत, आर्मीनिया ने दूरी बनाए रखी और प्रतिशोध में कार्रवाई नहीं की। रूस के हस्तक्षेप से चौबीस घंटे के भीतर हुए युद्धविराम समझौते में आर्मीनिया भी शामिल नहीं था।

प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आर्मीनिया ने काराबाख आर्मीनियाई लोगों के मुद्दे को छोड़ दिया है और संबंधों को सामान्य बनाकर क्षेत्र में स्थायी शांति की तलाश में अज़रबैजान के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ गया है; यह 7 दिसंबर 2023 के संयुक्त आर्मीनिया- अज़रबैजान बयान में परिलक्षित होता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है: "आर्मीनिया गणराज्य और अज़रबैजान गणराज्य इस विचार को साझा करते हैं कि क्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित शांति हासिल करने का एक ऐतिहासिक मौका है। *दोनों देशों ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के सम्मान के आधार पर संबंधों को सामान्य बनाने और शांति संधि तक पहुंचने के अपने इरादे की पुष्टि की।*"

संयुक्त बयान एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ था क्योंकि यह अपनी तरह का पहला दस्तावेज़ था जहाँ कोई भी मध्यस्थ बयान में पक्षकर नहीं है। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खत्म करने और इसे द्विपक्षी आधार पर निपटाने का फैसला किया है।

हालाँकि, उपलब्ध संकेतों के अनुसार, जर्मन ओएससीई मिन्स्क समूह द्वारा दावा किए गए स्थानों पर चले गए हैं। जर्मन चांसलर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर आर्मीनिया के प्रधानमंत्री और अज़रबैजान के राष्ट्रपति

(17 फरवरी 2024) के साथ बैठक की और शांति वार्ता के परिणाम में दोनों देशों को (यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के साथ) मदद करने के लिए जर्मनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। कुछ ही समय के भीतर, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आर्मीनिया और अज़रबैजान के विदेश मंत्रियों ने जर्मनी द्वारा आयोजित एक बैठक में बर्लिन में मुलाकात की।

इस क्षेत्र में भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं। साहित्यिक साक्ष्य आर्मीनिया में 149 ई.पू. में हिंदू बस्तियों की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। देवनागरी और गुरुमुखी में शिलालेखों और भगवान शिव के त्रिशूल के प्रतीकों के साथ बाकू के पास ज्वाला मंदिर मध्ययुगीन काल में मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजनों के लिए इस क्षेत्र में भारतीयों की उपस्थिति का जीवित वास्तुशिल्प प्रमाण है। आर्मीनियाई, जॉर्जियाई और अज़ेरिस भारत में, विशेष रूप से मध्यकाल से लेकर स्वतंत्रता पूर्व काल तक, अपनी उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाते थे। भारत में आर्मीनियाई लोगों द्वारा बनाया गया चर्च और गिरजाघर आज तक खड़े हैं और भारत में उनके गौरवशाली अतीत के प्रतीक हैं।

इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों का आधुनिक इतिहास 1992 में शुरू हुआ जब भारत ने आर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दी और उनसे राजनयिक संबंध बनाए। साल 1992 के बाद की अवधि में, भारत ने आर्मीनिया के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और रक्षा संबंध बनाए हैं; यह आर्मीनिया के राष्ट्रपति की भारत के तीन दौरों और भारत से आर्मीनिया में उपराष्ट्रपति स्तर की इतनी ही यात्राओं में परिलक्षित होता है। आर्मीनिया इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारत ने 30 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापनों के अलावा "मैत्री और सहयोग संधि" (1995) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके विपरीत, कुछ बाहरी और विदेशी कारणों ने अज़रबैजान और जॉर्जिया के साथ राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने में बाधा उत्पन्न की है। राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख स्तर पर एक भी उच्चस्तरीय बैठक नहीं हुई है।

द्विपक्षीय बातचीत वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर संस्थागत व्यवस्था, जैसे विदेश मंत्रालय परामर्श/ अंतर- सरकारी आयोगों तक ही सीमित है।

अज़रबैजान के मामले में, पर्याप्त उच्च स्तरीय राजनीतिक समझ की कमी के लिए सबसे स्वीकार्य स्पष्टीकरण यह है कि अज़रबैजान पाकिस्तान के बहुत करीब है और अक्सर ओआईसी के भीतर और बाहर कश्मीर मुद्दे को उठाने में पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करता है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रक्षा संबंध भी हैं।

रूस के साथ जॉर्जिया के संबंध, विशेष रूप से 2008 के युद्ध और जॉर्जियों के दो अलग क्षेत्रों (अब्रखज़िया और दक्षिण ओसेतिया) के लिए रूस के समर्थन के बाद से तनावपूर्ण बने हुए हैं। संभवतः, रूस की संवेदनशीलता के सम्मान में भारत ने काफी समय तक जॉर्जिया के साथ अपने संबंधों को ठंडे बस्ते में रखा, अब कुछ परोध संकेत मिल रहे हैं, जो जुलाई 2021 में भारत के विदेश मंत्री की जॉर्जिया यात्रा में परिलक्षित होते हैं, कि, भारत द्विपक्षीय संबंधों को कुछ गति प्रदान करने पर विचार कर रहा है। त्बिलिसी में एक स्थानिक राजनयिक मिशन की स्थापना अगला कदम हो सकता है। अज़रबैजान के मामले में ऐसे कोई संकेत नज़र नहीं आर रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक निकटता के स्तर और व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के स्तर के बीच कोई सह- संबंध नहीं है। क्षेत्र में व्यापार और निवेश को निजी क्षेत्र के समग्र व्यावसायिक अवसरों के आकलन द्वारा अधिक निर्देशित किया गया है। जॉर्जिया के अपेक्षाकृत स्थिर लोकतंत्र और व्यापार करने में आसानी जैसे मामलों में उच्च अंतरराष्ट्रीय रेटिंग ने भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को इस्पात, बुनियादी ढांचे, कृषि और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। अज़रबैजान में, भारतीय निजी क्षेत्र ने फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश किया है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अज़रबैजान में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया है। अक्टूबर 2023 में, प्रयोगशाला में विकसित हीरा उत्पादन उद्योग और प्राकृतिक हीरा प्रंसस्करण बुनियादी ढांचे को लॉन्च करने

और भारत एवं अज़रबैजान के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करने के अवसरों की पहचान करने के लिए अज़र गोल्ड, अज़रबैजान इन्वेस्टमेंट और गुजरात में सूरत स्थित कंपनी देवंगी इनोवेशन एलएलपी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत के दृष्टिकोण से, यह क्षेत्र अच्छे अवसर प्रदान करता है। जॉर्जिया और अज़रबैजान दोनों का अब भारत के साथ सीधा हवाई संपर्क है, जो व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक सक्षम कारक है। जॉर्जिया यूरोपीय संघ के साथ अपने एसोसिएशन समझौते और गहरे एवं व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए महत्व रखता है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ- साथ एकल बाज़ार के रूप में यूरोपीय संघ के साथ जॉर्जिया के उत्तरोत्तर पूर्ण एकीकरण को सुविधाजनक बनाना है। इस संदर्भ में, मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने का भारत का निर्णय भविष्यवादी है और इसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के अलावा, अज़रबैजान को दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय परिवहन परियोजनाओं के लिए रणनीतिक स्थान प्राप्त है: अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी/ INSTC) और पूर्व पश्चिम परिवहन गलियारा। दो अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारे उत्तर को दक्षिण और पूर्व को पश्चिम से जोड़ने के लिए हैं।
भारत की आईएनएसटीसी में हिस्सेदारी है, जो मुंबई को मध्य एशिया और अज़रबैजान के रास्ते रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है।
इसके अलावा बाकू (अज़रबैजान)- त्बिलिसी (जॉर्जिया)- कार्स (तुर्की) रेल लिंक (जो 2017 में चालू हो गया) का उपयोग अज़रबैजान के रास्ते तुर्की और यूरोप में माल के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह (भारत की मदद से विकसित) को आईएनएसटीसी (INSTC) में जोड़ने के लिए आर्मीनिया के मामले पर ज़ोर दे रहा है।

आर्मीनिया भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों के खरीददार के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा, खनन क्षेत्र (सोना और तांबा) में, भारत में अन्वेषण और आयात के लिए, अवसर मौजूद हैं।

मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा:

- दक्षिण कौकसस एक जटिल क्षेत्र है, जहाँ अंतर- क्षेत्रीय और अंतर- क्षेत्रीय युद्धों ने इसके एकीकरण में बाधा उत्पन्न की है। पूर्व और पश्चिम के चौराहे पर इसका स्थान और इसके प्राकृतिक संसाधन इस क्षेत्र को भू- राजनीतिक और आर्थिक महत्व प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र ने वैश्विक खिलाड़ियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है;

- साल 1992 के बाद से बहुत समय तक रूस, अमेरिका और यूरोप ने रणनीतिक स्थान साझा किए।

.

- साल 2020 का दूसरा नागोर्नो- काराबाख युद्ध और 2023 में अज़रबैजान के सैन्य आक्रमण ने समीकरण बदल दिए हैं। युद्ध प्रबंधन/ समाधान में संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की भूमिका कम हो गई है लेकिन वे जॉर्जिया- अब्रखज़िया/ दक्षिण ओसेतिया युद्ध पर जिनेवा, अंतरराष्ट्रीय चर्चा में शामिल रहते हुए अन्य क्षेत्रों में इस क्षेत्र में अपने पदचिन्हों को मजबूत करना जारी रखेंगे;

- रूस प्रासंगिक बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करेगा जिस क्षेत्र को वह प्रभाव क्षेत्र मानता है;

- निकट भविष्य में दक्षिण कौकसस के रणनीतिक स्थल के और अधिक भीड़भाड़ वाले होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जर्मन पहले ही आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच शांति संधि की दिशा में बातचीत में मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तुर्की बड़ी भूमिका हासिल करने की प्रतीक्षा में है। ईरान घटनाक्रम पर अपनी करीबी नज़र बनाए हुए है। फ्रांस आर्मीनिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प और स्पष्ट है;

- आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच शांति संधि की राह लंबी और कठिन हो सकती है, खासकर अगर अज़रबैजान दक्षिणी प्रांत स्युनिक से गुजरने वाले परिवहन गलियारे पर संप्रभुता के लिए अपना दावा पेश करता है। अज़ेरियाई इसे ज़ंगेज़ुर कॉरिडोर करना शुरू कर चुके हैं (ज़ंगेज़ुर) अज़रबैजान द्वारा स्युनिक को दिया गया वैकल्पिक नाम है।

नवंबर 2020 समझौते के तहत, आर्मीनिया ने अज़रबैजान की मुख्य भूमि और अर्मीनियाई क्षेत्र द्वारा अलग किए गए अज़रबैजान के एक्सक्लेव नखिचेवन के बीच एक सड़क संपर्क प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। मार्ग के संरेखण पर कोई विवरण नहीं दिया गया था लेकिन स्युनिक से होकर गुजरने वाला रास्ता सबसे छोटा है और सोवियत काल के दौरान इस पर आवाजाही हुआ करती थी। ऐसी आशंकाएं हैं कि स्युनिक आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच एक और विवाद का विषय बन सकता है।

- आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच संबंधों के सामान्यीकरण से आर्मीनिया और तुर्की के बीच संबंधों के सामान्य होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है; वर्तमान में दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं हैं;
- अपने अलग हुए क्षेत्रों के साथ जॉर्जिया का विवाद अनसुलझा है और निकट भविष्य में भी स्थिति ऐसी ही बने रहने की संभावना है;
- भारत कच्चे माल, रक्षा आपूर्ति गंतव्य, ऊर्जा स्रोतों और रूस एवं यूरोप के साथ कनेक्टिवी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस क्षेत्र के महत्व को महसूस करता है। नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, एक्ट वेस्ट, सेंट्रल एशिया कनेक्ट के विपरीत भारत के पास विशेष रूप से स्पष्ट दक्षिण कौकसस नीति नहीं है; शायद इसकी जरूरत नहीं है। निकट भविष्य में, तीनों देशों में से प्रत्येक के साथ राजनीतिक संबंध गुणों के आधार पर विकसित होते रहने की संभावना है। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर अज़रबैजान की बयानबाज़ी के अलावा, अज़रबैजान के साथ या उस मामले में तीनों देशों में से किसी के साथ कोई अन्य गंभीर द्विपक्षीय विवाद नहीं है।

निकट भविष्य में जॉर्जिया के साथ राजनीतिक संपर्क के स्तर में

कुछ वृद्धि देखी जा सकती है; अज़रबैजान के मामले में फिलहाल ऐसे कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं।

- क्षेत्र में अलग- अलग देशों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों का स्तर बाज़ार ताकतों द्वारा निर्देशित होने की संभावना है और उच्च स्तर पर राजनीतिक निकटता के स्तर के कम होने के बावजूद, अज़रबैजान और जॉर्जिया दोनों को अपना उचित हिस्सा मिलेगा।

प्रो. अजय पटनायक

दक्षिण कौकसस में बदलती स्थितियाँ और इसके प्रभावों पर एक पैनल चर्चा आयोजित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह को हार्दिक धन्यवाद। पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए विद्वानों को एक मंच पर जुटाने के लिए डॉ. अतहर ज़फ़र विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

पिछले लगभग साढ़े तीन दशकों में दक्षिण कौकसस, जिसे ट्रांस- कौकसस भी कहा जाता है, ने, ऐसे युद्ध देखे हैं जिनसे तीन देश- जॉर्जिया, आर्मीनिया और अज़रबैजान प्रभावित हुए हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच का युद्ध जो 1992 की शुरुआत में पूर्ण पैमाने पर लड़े जाने वाला युद्ध बन गया था, के कारण, बड़े पैमाने पर आर्मीनिया और अज़ेरी के निवासियों का पलायन हुआ। दोनों ही गणराज्य जातीय रूप से लगभग एक जैसे हो गए हैं, अज़रबैजान में आर्मीनिया का कोई निवासी नहीं है और आर्मीनिया में कोई अज़ेरी नहीं है। युद्धों ने बाहरी दुनिया से उनके संबंधों को भी प्रभावित किया है।

अज़रबैजान की कोई सीमा तुर्की से नहीं लगती और आर्मीनिया की सीमा तुर्की से लगता है लेकिन वह अज़रबैजान को अपनी सीमा से तुर्की के लिए रास्ता नहीं देता। अज़रबैजान के लिए केवल एक ही विकल्प है- जॉर्जिया, जिसके कारण अज़ेरी तेल को यूरोप ले जाने के लिए बाकू- त्बिलिसी- सेहान (बीटीसी/ BTC) पाइपलाइन के लिए जॉर्जिया के रास्ते लंबे मार्ग पर विचार किया गया था।

जब सोवियत संघ अपने अंतिम दिनों में था, तब राष्ट्रवाद देश की एक बड़ी समस्या बन गया था और इसके बाद सोवियत गणराज्य के बाद प्रत्येक घटक के भीतर राजनीति का निर्धारण हुआ। प्रत्येक देश में नेतृत्व ने बहुसंख्यकवादी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने का प्रयास किया। जब अल्पसंख्यक आबादी ने इन विकासों का विरोध किया तो उन्हें या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या दबा दिया गया। अल्पसंख्यक आबादी के बीच स्वतंत्रता और अलग राज्य की मांग उठी

राष्ट्रवाद ने सोवियत द्वारा खींची गई सीमाओं को भी चुनौती दी जिसके कारण युद्ध और सीमा विवाद हुए।

जॉर्जिया में दो पूर्व स्वायत्त क्षेत्रों- अब्रखज़िया और दक्षिण ओसेतिया, ने, अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के साथ त्बिलिसी में नए राष्ट्रीयकरण नेतृत्व के तहत अपनी स्वायत्तता खोने के बाद विद्रोह कर दिया। 1990 के दशक के आरंभ में जमे हुए संघर्ष (फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट) के बाद, 2008 में वृद्धि के कारण रूस के साथ युद्ध हुआ जिसका नतीजा ये हुआ कि जॉर्जिया ने उपरोक्त दोनों क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता खो दी, जो स्वतंत्र हो गए, उन्होंने रूस का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की है। हालाँकि, रूस ने इन दोनों संस्थाओं को शामिल नहीं किया है लेकिन मॉस्को ने वहां सेना रखकर व्यावहारिक रूप से अपनी रक्षा सीमाओं का विस्तार किया है।
रूस के साथ जॉर्जिया की सीमा सिकुड़ गई है और सीमा पार संबंध भी कम हो गए हैं। रूस ने न केवल अब्रखज़िया और दक्षिण ओसेतिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी, बल्कि दोनों में सेना और सैन्य उपकरण तैनात किए।

जैसे ही जॉर्जिया रूस से अलग हुआ, पश्चिम ने हस्तक्षेप किया। पश्चिम ने जब अज़रबैजान से तुर्की तक अज़ेरी तेल ले जाने वाली बीटीसी पाइपलाइन का समर्थन किया तब जॉर्जिया को लाभ हुआ। चूँकि पारगमन देश की सीमाएँ अन्य दो देशों के साथ लगती हैं, जॉर्जिया को इस मार्ग से आर्थिक रूप से लाभ होता है। यह अमेरिकी प्रायोजित गुआम (जॉर्जिया, यूक्रेन, अज़रबैजान और मोल्दोवा) क्षेत्रीय समूह में भी शामिल हो गया। फरवरी 2022 से यूक्रेन में रूस की विशेष अभियानों के बाद, जॉर्जिया पर रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ सक्रिए रूप से सहयोग करने का दबाव बढ़ गया है।

आर्मीनिया- अज़रबैजान युद्धः 1923 में, सोवियत संघ ने अज़रबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य में 95 जातीय आर्मीनियाई आबादी के साथ नागोर्नो- काराब्राख स्वायत्त ओब्लास्ट की स्थापना की। नागोर्नो- काराब्राख की क्षेत्रीय विधायिका ने 1988 में एक प्रस्ताव पारित कर अज़रबैजान के भीतर अपने आधिकारिक स्थान के बावजूद, आर्मीनिया गणराज्य में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा की। जातीय तनाव का एक लंबा इतिहास रखने वाले दोनों गणराज्यों के बीच सशस्त्र लड़ाई को सोवियत शासन के दौरान नियंत्रण में रखा गया था।

लेकिन जैसे- जैसे सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ, वैसे- वैसे इस क्षेत्र में शांति भी बढ़ने लगी। साल 1991 में सोवियत विघटन के बीच, जैसे ही आर्मीनिया और अज़रबैजान ने राष्ट्र का दर्जा हासिक किया, नागोर्नो- काराब़ाख ने आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग हताहत हुए और सैकड़ों हज़ारों शरणार्थी बन गए। साल 1993 तक, आर्मीनिया ने नागोर्नो- काराब़ाख पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। साल 1994 में, रूस ने बिश्केक प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाने वाला युद्धविराम किया, जिससे नागोर्नो- काराब़ाख वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो गया, स्टेपानाकर्ट में एक स्व-घोषित सरकार बनी, लेकिन अभी भी यह आर्मीनिया के साथ घनिष्ठ आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंधों पर बहुत अधिक निर्भर है।

साल 1994 में जब युद्ध बंद हुआ, नागोर्नो- काराब़ाख और सात निकटवर्ती जिले पूरी तरह से या आंशिक रूप से आर्मीनियाई सेना के नियंत्रण में थे। दस लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से बाहर कर दिया गया थाः अज़रबैजान के निवासी आर्मीनिया, नागोर्नो- काराब़ाख और आस- पास के इलाकों से भाग गए जबकि आर्मीनिया के लोगों ने अज़रबैजान में अपने घरों को छोड़ दिया।

मुख्य रूप से यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई/OSCE) के मिन्स्क समूह के नेतृत्व में बातचीत और मध्यस्थता के प्रयास, युद्ध का स्थायी समाधान निकालने में विफल रहे। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1994 में मिन्स्क समूह बनाया गया था और इसकी सह- अध्यक्षता अमेरिका, फ्रांस और रूस ने की थी। हालाँकि समूह ने सफलतापूर्वक युद्धविराम पर बातचीत की लेकिन क्षेत्रीय विवाद कठिन बने रहे।

मिन्स्क समूह के प्रयासों के कारण, आर्मीनिया- अज़रबैजान युद्ध एक “जमा हुआ संघर्ष/फ्रोज़न कॉन्फिल्क्ट” बन गया, हालांकि अप्रैल 2016 में चार दिनों के जबरदस्त युद्ध समेत लड़ाई की छिटपुट घटनाएं हुईं, जिसमें दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन यह 27 सितंबर 2020 की घटना थी जब फिर से युद्ध छिड़ गया जो 10 नवंबर तक चला। रूस की मध्यस्थता से हुए समझौते से युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप

अज़रबैजान को नागोर्नो- काराब़ाख के बड़े हिस्से समेत सात निकटवर्ती जिलों का फायदा हुआ। आर्मीनिया पूर्व सोवियत नागोर्नो- काराब़ाख स्वायत्त ओब्लास्ट के बाहर सभी कब्जे वाले क्षेत्र को अज़रबैजान को वापस करने पर सहमत हुआ।
रूसी शांति सैनिकों को युद्धविराम की निगरानी के लिए और तथाकथित "लाचिन कॉरिडोर" के माध्यम से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया था जो नागोर्नो- काराब़ाख को आर्मीनिया से अलग करता है।

एक और क्षेत्र है, नखचिवन स्वायत्त गणराज्य, जो वार्ता का केंद्र रहा है। अज़रबैजान का एक भूमि से घिरा इलाका, नखचिवन की सीमा आर्मीनिया, ईरान और तुर्की से लगती है। हालाँकि, एक्सक्लेव की अज़रबैजान के साथ कोई सीमा नहीं है। युद्ध के कारण, अज़रबैजान को एक्सक्लेव के साथ आर्थिक और परिवहन संबंध बनाना मुश्किल हो गया।

साल 2020 के युद्धविराम समझौते के हिस्से के रूप में, जिसने दूसरे नागोर्नो- काराब़ाख युद्ध को समाप्त कर दिया, आर्मीनिया दोनों देशों के बीच लोगों, वाहनों और कार्गो की आवाजाही की अनुमति देने पर सहमत हुआ, इस प्रकार अज़रबैजान के पश्चिमी क्षेत्रों को नखचिवन से जुड़ने की सुविधा मिली। एक्सक्लेव को अज़रबैजान से जोड़ने वाले गलियारे के माध्यम से सुरक्षित आवाजाही पर रूस की सीमा सेवा द्वारा गश्त की जाएगी।

हालाँकि, युद्धविराम केवल अस्थायी था; 13-14 सितंबर 2022 को फिर से युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और गिरफ्तारियां हुईं। आखिरकार सितंबर 2023 में, लाचिन गलियारे की एक महीने लंबी चली नाकाबंदी के बाद अज़रबैजान की सेना ने तेज़ी से इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। बहुसंख्यक जातीय आर्मीनियाई नागोर्नो- काराब़ाख से भाग गए, जिसे 2024 की शुरुआत तक पूरी तरह से अज़रबैजान में शामिल कर लिया गया था।

सोवियत संघ के बाद के अंतरिक्ष में राष्ट्रवाद की राजनीति ने न केवल अंतर-देशीय बल्कि प्रत्येक गणराज्य में रहने वाली राष्ट्रीयताओं/जातीय समूहों के बीच दूरियों को बढ़ा कर राज्यों के भीतर संबंधों को प्रभावित किया। देशों के बीच और देशों में विवादों ने बाहरी देशों को उनके भू- राजनीतिक एवं रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया।

अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश मुख्य पात्र हैं। आर्मीनिया- अज़रबैजान के संदर्भ में, तुर्की और ईरान सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय कारकों के कारण शामिल रहे हैं। यूरेशियाई शक्ति के रूप में रूस सोवियत काल के बाद की भू- राजनीति में एक निरंतर कारक रहा है।

साल 1994 के आखिर में कौकसस और मध्य एशियाई क्षेत्रों में अमेरिकी रणनीतिक हितों में एक नाटकीय बदलाव आया, जब अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कैस्पियन सागर के तेल भंडार की क्षमता लगभग 200 बिलियन बैरल होने का अनुमान लगाते हुए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसने इसे सऊदी के भंडार से तुलनीय बना दिया।

अमेरिकी नीति बाद में सैन्य भागीदारी समेत अमेरिकी भागीदारी को बढ़ाकर, अमेरिका के अनुकूल शासन और नीतियों को बढ़ावा देकर और मुक्त बाजार, व्यापार उदारीकरण एवं पश्चिम निवेश को प्रेरित कर कौकसस/मध्य एशियाई राज्यों को यूरो- अटलांटिक क्षेत्र में एकीकृत करने की तरफ बढ़ी। प्रमुख गैर- रूसी राष्ट्रों के माध्यम से "यूरेशियन हार्टलैंड" को नियंत्रित/ प्रभावित करने के बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा एक भू-राजनीतिक वस्तु बन गई।

उस समय से जब क्लिंकन के शासन में वाशिंगटन ने तत्कालीन उप- सचिव, स्ट्रोब टैलबोट (ऊर्जा और वाणिज्य विभागों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सीआईए के प्रतिनिधियों के साथ) की अध्यक्षता में एक कैस्पियन टास्क फोर्स बनाई थी, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में रूस को हाशिए पर रखना था। तब से अमेरिकी प्रयासों में मध्य एशिया और कौकसस क्षेत्रों में वैकल्पिक तेल मार्गों को खोजने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में भविष्य में नाटो के विस्तार की संभावना का पता लगाने के सभी प्रयास शामिल हैं। इस तरगह के कदम सीधे तौर पर रूसी, चीनी और ईरानी हितों को कमजोर करते हैं। क्लिंटन प्रशासन के दिनों से, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने पूर्व सोवियत गणराज्यों को पश्चिमी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संस्थानों एवं

संरचनाओं में एकीकरण को एक मौलिक नीति उद्देश्य बना दिया है।

संयुक्त नाटो- पीएफपी (शांति हेतु साझेदारी) कार्यक्रम के तहत 1997 से इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। नाटो ने उत्तरी अमेरिकी सहयोग परिषद (एनएसीसी/ NACC) भी बनाई। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहा दिसंबर 1995 में नाटो और यूएस सेंटकॉम (मध्य कमान) के तत्वाधान में, शांति बनाए रखने एवं युद्ध-प्रबंधन में जनादेश के साथ मध्य एशियाई बटालियन का गठन। बटालियन की स्थापना पीएफपी और एनएसीसी एवं उज़्बेकिस्तान के सैनिकों की भागीदारी से की गई थी।

दो वैश्विक शक्तियों- रूस और अमेरिका के बीच खींचातानी में, यूरेशिया के नव स्वतंत्र राज्यों ने स्वयं को इस या उस तरफ झुकाव के लिए लालची या विवश पाया है। खेल जीरो सम का है। एक को होने वाला लाभ दूसरे के लिए समान मात्रा में हानि के रूप में देखा जाता है। हालाँकि, रूस ने इस क्षेत्र में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त की, अमेरिका ने शासन परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए गैर- सरकारी नेटवर्क बनाकर इन राज्यों को अधिक सूक्ष्म तरीके से अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। जॉर्जिया (रोज रेवलूशन 2003), यूक्रेन (ऑरेंज रेवलूशन 2004) और किर्गिस्तान (ट्यूलिप रेवलूशन 2005) में सफल शासन परिवर्तन उतना ही आंतरिक असंतोष का परिणाम था जितना बाहरी युद्ध का।

तथाकथित 'रोज़ रेवलूशन' के बाद, जॉर्जिया में एक अमेरिकी समर्थक शासन सत्ता में आया और मिखाइल साकाश्विली राष्ट्रपति बने। इसने नाटो सदस्यता के लिए बहुत दबाव डाला।
रूस- जॉर्जिया संबंध इतने बिगड़ गए कि अगस्त 2008 में उनके बीच युद्ध हो गया। कुछ जमे हुए झगड़े फिर से जीवंत हो उठे। ऊर्जा और पाइपलाइन मार्ग भू-राजनीतिक मुद्दों में बदल गए। अमेरिका ने कैस्पियन क्षेत्र में हथियारों की होड़ शुरू कर दी। यह क्षेत्र को अमेरिकी और नाटो सैन्य सहायता के माध्यम से संभव हुआ जो बढ़ती रही। ऐसे में जबकि अमेरिकी सैन्य सहायता ने अज़रबैजान को अपनी नौसैनिक क्षमताओं का निर्माण करने में मदद की, इसने

‘कैस्पियन में स्थायी अमेरिकी उपस्थिति के लिए जमीनी कार्य’ भी किया। इसके अलावा, अज़रबैजान को हथियार देने से कैस्पियन और कौकसस क्षेत्रों में ईरानी प्रभाव का मुकाबला करने में मदद मिली।

जॉर्जिया की तरह अज़रबैजान के नेताओं ने भी सैन्य ठिकानों समेत नाटो की भागीदारी में गहरी दिलचस्पी दिखाई। जॉर्जिया में अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षकों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की शुरूआत के बाद, अज़रबैजान में एक बड़ी अमेरिकी उपस्थिति की उम्मीदें बढ़ीं, खासकर अगर अमेरिका के पास फारस की खाड़ी में ईरान के खिलाफ युद्ध गतिविधियों की योजना थी। मार्च 2002 के अंत में बाकू में द्विपक्षीय सैन्य परामर्श के साथ शुरुआत करते हुए, दोनों ने कैस्पियन में नौसैनिक रक्षा, वायु नियंत्रण के मानकीकरण और अज़रबैजान के सैनिकों के सैन्य प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया।

मई 1992 में जब आर्मीनिया रूस के नेतृत्व वाली सामूहिक सुरक्षा संधि में शामिल हुआ, तो उसी महीने अज़रबैजान स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल समूह से हट गया (हालांकि बाद में यह फिर से संगठन में शामिल हो गया। इसी प्रकार, दक्षिण ओसेतिया और अब्रखज़िया की रूसी संघ में शामिल होने की इच्छा को जॉर्जिया ने रूस द्वारा देश को विभाजित और कमज़ोर बनाने की चाल माना था। यहाँ तक की जॉर्जिया के साथ एक समझौते के तहत संयुक्त शांति स्थापना ने बी रूस को अछूता नहीं छोड़ा। उस पर जॉर्जिया के साथ दो अलग हुए क्षेत्रों के एकीकरण को रोकने के लिए शांति- रक्षा को एक साधन के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। युद्धों में अज़रबैजान और जॉर्जिया में जीत में असमर्थता ने रूस और इन दो कौकसस देशों के बीच खाई पैदा कर दी। इससे अमेरिका को रूस को नियंत्रित करने की अपनी रणनीति को आकार देने का अवसर मिला।

सांस्कृतिक और भौगोलिक कारकों के कारण तुर्की और ईरान दोनों ही के कौकसस में गहरी दिलचस्पी है। ईरान की सीमा अज़रबैजान से लगती है, जहां बहुसंख्यक शिया आबादी है जो जातीय रूप से तुर्क हैं। तुर्की की सीमा आर्मीनिया से लगती है जो 2013 में उस्मान के तुर्कों द्वारा आर्मीनिया के लोगों के ‘नरसंहार' का मुद्दा लगातार उठाता रहता है। सोवियत विघटन के बाद से, तुर्की ने 1990 के दशक में तुर्की समुदायों तक पहुंचने की नीति अपनाई। मध्य एशिया में

भू- राजनीतिक शून्य को भरने के लिए 'तुर्की मॉडल' एक आकर्षक संभावित साधन के रूप में सामने आया। मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्यों में रहने वाले साठ मिलियन (छह करोड़) तुर्कों के साथ इक्कीसवीं सदी के 'तुर्क सदी' बनने की भी चर्चा थी। 1990 के दशक के दौरान ऐसी भी अटकलें थीं कि तुर्की पूरे मध्य एशिया में राष्ट्र निर्माण हेतु एक आदर्श पेश करेगा।

अज़रबैजान, जो आर्मीनिया के साथ युद्ध कर रहा था, स्वाभाविक रूस से तुर्की का पक्षधर था। इस प्रक्रिया को तब मदद मिली जब पश्चिम ने रूस को दरकिनार कर यूरोप तक कैस्पियन ऊर्जा के मार्ग के रूप में तुर्की को प्राथमिकता दी। कई परियोजनाओं, विशेष रूप से बाकू- त्बिलिसी- सेहान तेल, बाकू- त्बिलिसी- अज़ुरम गैर पाइपलाइन, बाकु- त्बिलिसी- कार्स रेलवे, ने बाकू और अंकारा के बीच सुधरते संबंधों में योगदान दिया है। आर्मीनिया के पास इस क्षेत्र में तुर्की के लिए ऐसा कोई लाभ नहीं था।

दक्षिण कौकसस की भू-राजनीति में ईरान एक अन्य खिलाड़ी है। तेहरान की धार्मिक विचारों द्वारा निर्देशित होने की अनिच्छा के कारण अज़रबैजान के साथ इसके संबंध खराब हो गए। युद्ध के प्रति ईरान की नीति जातीय विचारों से अधिक प्रभावित है। ईरान की एक तिहाई आबादी अज़ेरी है और ईरान में अज़ेरी राष्ट्रवादियों की अतार्किक गतिविधियों के लिए बाकू के समर्थन ने तेहरान को नाराज़ कर दिया है।

इन समस्याओं के बावजूद, ईरान- अज़रबैजान संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे थे और 1995 की शुरुआत तक ईरान अज़रबैजान का प्रमुख विदेशी आर्थिक भागीदार था। ईरान भी "सदी के अनुबंध" में भागीदार था, जिसे अज़रबैजान के कैस्पियन तेल संसाधनों का पता लगाने के लिए गठित एक अंतरराष्ट्रीय तेल संघ को प्रदान किया गया था। ईरान ने आर्मीनिया के साथ युद्ध के कठिन दौर में अज़रबैजान की मदद की जब युद्ध के मैदान में आर्मीनिया की सफलताओं के बाद तेहरान ने 21 मार्च 1992 को युद्धविराम पर बातचीत की। मई 1992 में तेहरान में शांति वार्ता आयोजित की गई थी, जो हालांकि,

विफल हो गई क्योंकि आर्मीनिया ने शुशा पर कब्ज़ा कर लिया था और इस तरह काराब़ाख से आगे के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था।

दोनों देशों के बीच संबंधों में तब नकारात्मक मोड़ आ गया जब अमेरिका के दबाव में अज़रबैजान ने कंसोर्टियम में भागीदार के रूप में ईरान को हटाने और इसके बदले अमेरिकी और तुर्की के कंपनियों को अधिक हिस्सेदारी देने का फैसला किया। (अज़रबैजान का हिस्सा स्थानांतरित करके एक्सॉन को 5 प्रतिशत हिस्सा दिया गया और तुर्की पेट्रोलियम का हिस्सा 1.7 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया)। इस कदम ने पुष्टि कर दी कि कैस्पियन में अमेरिकी कदम ईरान के लिए केवल ज़ीरो सम हो सकते हैं। ईरान ने तत्काल इस मुद्दे को उठाया।

1990 के दशक के मध्यम में, अपने देश पर संभावित अमेरिकी हमले के ईरान के डर को देखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अज़रबैजान के सैन्य प्रस्ताव ने ईरान को भविष्य की आक्रामकता से खुद को सुरक्षित करने के लिए जवाबी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अज़रबैजान के पास मध्य एशिया और पश्चिम एशिया दोनों में अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक प्रभाव डालने में मदद करने की क्षमता थी। अज़रबैजान के साथ ईरान की समुद्री और भूमि सीमा ने उसे अमेरिकी डिजाइनों और चालों के प्रति और भी अधिक असुरक्षित महसूस करवाया।

कैस्पियन और उसके पड़ोस में अमेरिका के दबाव में अज़रबैजान- रूस संबंधों में हो रहे सुधार को भी नुकसान पहुंचा। अज़रबैजान ने बीटीसी पाइपलाइन, जीयूएएम ग्रुपिंग, कैस्पियन में अमेरिकी सैनिकों, प्रशिक्षकों और औज़ारों की तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2001 से, अगर अज़रबैजान की नाटो में शामिल होने की इच्छा पूरी हो जाती है या वह अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों का मेज़बान बन जाता है तो स्वाभाविक है कि रूस को सुरक्षा संबंधी चिंताएं सताएंगी।

हालाँकि, इन घटनाक्रमों के बावजूद रूस ने कभी भी अज़रबैजान के साथ संबंध नहीं तोड़े। वास्तव में, अज़रबैजान के साथ उसके मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंध बने रहे।

चैथम हाउस शोध पत्र के अनुसार 1991 में मिली आज़ादी के बाद से अज़रबैजान का रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाने का प्रयास, रूस के पक्ष में बदल गया लगता है। ऐसा अज़रबैजान की सत्तारूढ़ सरकार के इस विश्वास के कारण हो सकता है कि रूस उन मुद्दों को हल कर सकता है जो अज़रबैजान के लिए महत्वपूर्ण हैं। रूस अन्य चीजों के अलावा अपने सॉफ्ट- पावर टूल का उपयोग कर इस धारणा को मजबूत करना चाहता है। चूँकि रूस ने जॉर्जिया के साथ 2008 के युद्ध के बाद दक्षिण कौकसस में अपनी शक्ति को बढ़ाया है, अज़रबैजान में नेतृत्व ने यह मानना शुरू कर दिया है कि उसे रूस की बढ़ती भू- राजनीतिक मुखरता से लाभ हो सकता है। रूस के सॉफ्ट- पावर टूल्स मास्को के लिए बाकू को प्रभावित करना आसान बनाते हैं। 2000 के दशक के उत्तरार्ध के आंकड़ों के अनुसार, दस लाख से अधिक अज़रबैजानी रूस में रहते हैं, जिनमें से आधे के पास रूसी नागरिकता या स्थायी निवास है, अन्य आधे को छोड़कर, जिसमें कानूनी/अवैध श्रमिक प्रवासी और मौसमी श्रमिक दोनों शामिल हैं। प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन अज़रबैजान के लाखों लोगों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह प्रवासी रूस और अज़रबैजान की मास्को तक पहुँच का लाभ उठा रहे हैं।

बीते कुछ वर्षों में संरेखण में कुछ बदलाव देखे गए हैं जो यूक्रेन में युद्ध से पहले और उसके दौरान सामने आए हैं। साल 2020 से अज़रबैजान की आक्रामकता को रोकने में सक्रिए रूप से शामिल होने से रूस का इनकार आर्मीनिया को अच्छा नहीं लगा है। जैसे ही पश्चिम के साथ अज़रबैजान की हिस्सेदारी में गिरावट आई, मास्को बाकू को लेकर जोश में आ गया। जॉर्जिया जिसने 2008 में रूस के गुस्से और अपने क्षेत्रों को हार जाने का सामना किया था, यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए उसी समय पश्चिम को आकर्षित करते हुए मास्को से जुड़ने के लिए कदम बढ़ा चुका था। वास्तव में, जॉर्जिया की यूरोपीय संघ की सदस्यता पर पश्चिम की प्रतिक्रिया से मदद नहीं मिली है।

रूसी विशेष अभियानों के बाद, यूक्रेन और मोल्दोवा को 2022 में यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिया गया था। हालाँकि, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन युद्ध के बाद से अधिक सकारात्मक रुख अपनाया है, जॉर्जिया को दिसंबर

2023 में ही उम्मीदवार का दर्जा दिया गया था। त्बिलिसी जाहिर तौर पर लोकतंत्र के मापदंडों पर कम पड़ गया। प्रमुख मुद्दा 'साकाशविली कारक' लगता है।

जॉर्जिया के लोकतंत्र-में कमी को उजागर करने के लिए यूरोप द्वारा साकाशविली मुद्दा उठाया गया है। 2000 के दशक में, जॉर्जिया के राष्ट्रपति साकाशविली और यूक्रेन के युशचेंको के तहत जॉर्जिया और यूक्रेन ने घनिष्ठ संबंधों का अनुभव किया। हालाँकि, 2013के चुनावों में हार के बाद, साकाशविली की यूएनएम पार्टी की जगह जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी ने ले ली।

"रोज़ रेवलूशन" के बाद दो बार (2003-2013) राष्ट्रपति रहे साकाशविली ने 2013 में हार के बाद जॉर्जिया छोड़ दिया और यूक्रेन में आश्रय लिया, जहाँ उन्हें ओडेसा का गवर्नर नियुक्त किया गया और फिर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की राष्ट्रीय सुधार परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया। जॉर्जिया में उन पर अनुपस्थिति में सत्ता के दुरुपयोग का मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराया गया। साल 2021 में जॉर्जिया लौटने पर साकाशविलीको को बंदी बना लिया गया। पश्चिम ने साकाशविली के जेल जाने और रिहाई को जॉर्जिया की लोकतंत्र साख के लिए परीक्षण बना दिया है। यह मुद्दा जॉर्जिया की ईयू सदस्यता के आड़े आता है।

जॉर्जियाई ड्रीम गवर्नमेंट के नज़रिए से, यूक्रेन की राजनीति में यूएनएम, विशेष रूप से साकाशविली की भागीदारी उनके द्विपक्षीय संबंधों में विवाद का एक प्रमुख बिन्दु थी। जॉर्जिया की सरकार यूक्रेन द्वारा साकाशविली को नागरिकता देने से विशेष रूप से चिढ़ गई थी और उन्हें ओडेसा ओब्लास्ट का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। इस बीच, यूक्रेन की सरकार ने तर्क दिया कि इस मुद्दे का उनके समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हालाँकि, "साकाशविली कारक" जॉर्जिया- यूक्रेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण विघटनकारी तत्व के रूप में उभरा।

यूक्रेन में युद्ध के बाद जो दूसरा मुद्दा सामने आया है, वह रूस पर प्रतिबंधों के प्रति त्बिलिसी की दुविधा है। जॉर्जिया की सरकार ने रूस के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सरकार ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन जा रहे जॉर्जिया के स्वयंसेवकों के एक विमान को भी रोक दिया।

जॉर्जिया ने रूसियों के आने को नहीं रोका, जो 2022 में, अनुमान के अनुसार, लगभग 100,000 था। जॉर्जिया की ओपन- डोर पॉलिसी रूस के लोगों के लिए प्रवेश और पारगमन दोनों की अनुमति देती है।
यूक्रेन युद्ध से पहले भी यही रिवाज था। साल 2008 में रूस- जॉर्जिया युद्ध के कुछ वर्षों के बाद, 2011 के बाद से जॉर्जिया जाने वाले रूसी नागरिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। जॉर्जियन नेशनल टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, 2019 में, वहां पंद्रह लाख (डेढ़ मिलियन) पर्यटक आए, जिससे करीब 70 करोड़ (700 मिलियन) अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। आर्थिक रूप से कमज़ोर जॉर्जिया उस आय को खोना नहीं चाहता था, भले ही इसके लिए जॉर्जिया में रूसियों का आना लगा रहे।

साल 2019 की गर्मियों में, जब कुछ लोगों ने जॉर्जिया के मामले में रूस के अनुचित हस्तक्षेप को लेकर त्बिलिसी में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू किया, तो रूस ने देश के लिए सीधी उड़ाने निलंबित कर दीं। उस समय, रूस के अधिकारियों ने अपने हमवतनों से जॉर्जिया छोड़ने का आग्रह किया और वहाँ की यात्रा न करने की सलाह दी। इसके कारण जॉर्जिया में रूसी पर्यटकों की संख्या कम हो गई, जिससे जॉर्जिया के पर्यटन उद्योग को गंभीर झटका लगा। हालाँकि, बाद में रूस के अधिकारियों ने उड़ान प्रतिबंध के मुद्दे पर फिर से विचार करने की मांग की। जनवरी 2023 के मध्यम में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से इस मुद्दे के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू हो सकती हैं, उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ अपने स्वयं के प्रतिबंध नहीं लगाने के जॉर्जिया के फैसले ने "सम्मान" अर्जित किया है।

हालाँकि, रूस के साथ जॉर्जिया की भू- सीमा (890 किमी से अधिक) खुली रही, जिससे अनेक रूसियों को देश में आने की अनुमति मिलती रही। कथित तौर पर, त्बिलिसी की सड़के, रेस्त्रां, बार और संग्रहालय रूसी भाषियों से भरे हुए हैं। साथ ही, रूस के साथ जॉर्जिया के बढ़ते आर्थिक संबंध यूक्रेन के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है: "यूक्रेन के नज़रिए से, रूस के साथ आर्थिक गतिविधि में शामिल कोई भी राज्य रूस की प्रतिबंधों से बचने और अपने सैन्य प्रयासों को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ावा देने का जोखिम उठाता है... इस संबंध में एक विशेष रूप से खतरनाक उदाहरण रूस के साथ सीधी उड़ानों को नवीनीकृत करने का जॉर्जिया का फैसला है, जिसमें अस्थायी रूस से कब्ज़े वाले क्रीमिया के लिए उड़ानों के संचालन के लिए

यूक्रेन द्वारा स्वीकृत कंपनियों को भी शामिल किया गया है।"

प्रतिबंधों का मज़ाक उड़ाने वाला एक दिलचस्प उदाहरण रूस के साथ जॉर्जिया की भू- सीमा के माध्यम से व्यापार है। जनवरी 2022 में, यूक्रेन में युद्ध से पहले, आर्मीनिया ने अमेरिका से 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कारों का आयात किया, जो एक साल बाद बढ़ कर 29.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का हो गया। तब से, दरों में वृद्धि जारी है। अप्रैल 2023 में, आर्मीनिया ने 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की अमेरिकी कारों का आयात किया। ये कारें (ज्यादातर सेकेंड हैंड) आखिरकार रूस में बेचे जाने के लिए थीं। वे मुख्य रूप से जॉर्जिया में पोटी के काला सागर बंदरगाह के रास्ते अमेरिका से आते हैं, फिर आर्मीनिया लाए जाते हैं जो यूरेशियन इकॉनमिक यूनियन के सदस्य के रूप में रूस के साथ एक सीमा शुल्क- मुक्त क्षेत्र साझा करता है। आर्मीनिया से वाहनों को सड़क मार्ग से, एक बार फिर जॉर्जिया को पार करते हुए, रूस भेजा जाता है।

हाल के दिनों में और विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध के बाद से आर्मीनिया- अज़रबैजान संदर्भ में भी कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। रणनीतिक साझेदारी संबंधों और दोनों देशों की प्रमुखों की नियमित आपसी यात्राओं से हाल के वर्षों में रूस और अज़रबैजान के संबंधों में काफी सुधार हुआ है। आंकड़ों के अनुसार 2017 और 2021 की पहली तिमाही के बीच, रूस अज़रबैजान का मुख्य व्यापारिक भागीदार रहा है (कुल व्यापार कारोबार में एक तिहाई और गैर- तेल क्षेत्र में पहला)। रूस अज़रबैजानी गैर- तेल उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है।

अज़रबैजान के साथ संबंध सुधारने की मास्को की इच्छा ने अप्रत्यक्ष रूप से बाकू की मदद की है। जैसे, दिसंबर 2022 में, अज़रबैजानी कार्यकर्ताओं ने नागोर्नो- काराबाख में अवैध खनन के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण का विरोध करते हुए लचिन कॉरिडोर को बंद कर दिया था। केवल एक हल्का-फुल्का बयान जारी करने के अलावा रूस के शांति रक्षकों ने राजमार्ग को सुरक्षित करने और उसे फिर से खुलवाने के लिए कुछ नहीं किया जबकि नागोर्नो- काराबाख में लोगों को गंभीर कमियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि मॉस्को युद्ध में पक्ष लेने को तैयार नहीं था; मॉस्को चाहता था

कि दोनों पक्ष एक शांति समझौते पर बातचीत करें जो दक्षिण कौकसस के इस हिस्से में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

1990 के दशक और 2000 के पहले दशक में बाकू के अमेरिका की ओर झुकाव के बावजूद, मॉस्को ने रेवन और बाकू दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास किया। आर्मीनिया सीएसटीओ (CSTO /सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन) और यूरेशियन आर्थिक संघ की सदस्य है। लेकन अज़रबैजान के साथ युद्ध में उसे रूस से प्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिला है। हर बार जब युद्ध भड़का, तो मॉस्को ने शांति- दूत के रूप में हस्तक्षेप किया, दोनों पक्षों को युद्धविराम समझौते पर लाया और दोनों युद्धरत सेनाओं के बीच सीमा पर रूस के सैनिकों को तैनात किया। इस संतुलन अधिनियम ने रूस को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, यहाँ तक कि उसके क्षेत्रीय सहयोगी आर्मीनिया के साथ भी तनाव पैदा हो गया है, जिसने सीएसटीओ में उसकी सदस्यता निलंबित करने की धमकी दी है। फिर भी, यूक्रेन में युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, रूस ने संघर्ष विराम में मध्यस्थता की जिससे 2023 का युद्ध समाप्त हुआ।

दूसरी ओर, अमेरिका जो रूस के खिलाफ अज़रबैजान को मजबूत कर रहा था, उसने हाल के दिनों में बाकू पर दबाव डाला है। साल 2022 के युद्ध के बाद के दिनों में, तत्कालीन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने नए सिरे से अमेरिकी प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में 17 सितंबर 2022 को आर्मीनिया में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने “अज़रबैजान द्वारा अवैध और घातक हमलों” की “कड़ी निंदा” की जिसे अज़रबैजान ने “आर्मीनिया का प्रचार” कह कर मानने से इनकार कर दिया। इससे युद्ध फिर से भड़क सकता है। कहा गया कि उनकी यात्रा ने अज़रबैजान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने के अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक प्रयासों को बाधित कर दिया है।

न केवल अमेरिका, बल्कि फ्रांस भी आर्मीनिया के पक्ष में कूद पड़ा है। हालाँकि बाकू ने अतीत में आर्मीनिया के पक्ष में पूर्वाग्रह के लिए फ्रांस की आलोचना की थी लेकिन आर्मीनिया द्वारा हार की नवीनतम श्रृंखला ने फ्रांस द्वारा अधिक सक्रिएसमर्थन को बढ़ावा दिया है। सितंबर- अक्टूबर 2023 में, अज़रबैजान द्वारा काराबाख पर कब्ज़ा करने के बाद से फ्रांस ने आर्मीनिया के साथ कई सैन्य सौदे हुए, जिसमें बख्तरबंद वाहन, हथियार, उपकरण और

युद्ध सामग्री प्रदान करना, साथ ही वायु- रक्षा क्षमताओं में सुधार करना शामिल है।

स्पष्ट रूप से यह अज़रबैजान के नेतृत्व को अच्छा नहीं लगा। 21 नवंबर 2023 को बाकू में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में फ्रांस की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति अलीव ने कहा, यह, "(फ्रांस) आर्मीनिया को हथियार देकर, आर्मीनिया में विद्रोही ताकतों को प्रेरित कर और हमारे क्षेत्र में नए सिरे से युद्ध को भड़काने के लिए ज़मीन तैयार कर एक सैन्यवादी नीति अपना रहा है"। बाकू ने आर्मीनिया के साथ सामान्यीकरण वार्ता में भाग लेने से भी इनकार कर दिया, जिसकी नवंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में योजना बनाई गई थी क्योंकि उसने इसे वाशिंगटन की "पक्षपातपूर्ण" स्थिति बताया था। अमेरिका और फ्रांस रूस के साथ सह- अध्यक्ष थे जिसने ओएससीई मिन्स्क समूह का नेतृत्व किया, जिसने 1990 के दशक में पहले युद्ध के अंत से 2020 तक शांति प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। नवीनतम काराबाख युद्ध में आर्मीनिया की हार ने रूस के साथ येरेवन के संबंधों में खटास ला दी। इस भू-राजनीतिक अवसर को न गंवाने की चाह में अमेरिका और फ्रांस ने येरेवन के साथ संबंधों को अधिक महत्व दिया।

साल 2020 के बाद से युद्धों के नवीनतम दौर में हार के बाद, आर्मीनिया भावी नुकसान को रोकने और अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने की उम्मीद में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा सहयोग के लिए वह फ्रांस के अलावा नई दिल्ली से भी संपर्क कर रहा है। हालाँकि भारत को दक्षिण कौकसस की भू- राजनीति में एक खिलाड़ी बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आर्मेनिया को कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्की और अज़रबैजान के खिलाफ नई दिल्ली की नाराजगी का फायदा उठाने की उम्मीद है। सहयोग को और बेहतर बनाने के लिए येरेवन द्वारा दिल्ली में एक रक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। साल 2020 में, भारत ने आर्मीनिया को हथियार- पता लगाने वाली स्वाति रडार प्रणाली बेची थी। उसके बाद, येरेवन को टैंक रोधी युद्ध सामग्री, पिनाका मल्टी- बैरल रॉकेट लॉन्चर और गोला- बारूद की आपूर्ति के लिए द्विपक्षीय समझौता भी किया गया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नवंबर 2022 में, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स ने आर्मीनिया को तोपखाने की आपूर्ति के लिए 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध प्राप्त किया।

आर्मीनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापिक्यन ने अक्टूबर 2022 में भारत का दौरा किया, उसके बाद आर्मीनिया के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर- जनरल एडवर्ड असरियान का दौरा हुआ और उन्होंने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान के साथ दिल्ली में बैठक की। इसके बाद अगस्त 2023 में आर्मीनिया के सुरक्षा परिषद के सचिव आर्मेन ग्रिगोरियन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक हुई। इस प्रकार के हाई-प्रोफाइल दौरे सहयोग को प्रगाढ़ करने की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रतीक हैं।

प्रमुख शक्तियों के एकजुट न होने के कारण कूटनीति अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकी। मई 2023 में अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस सभी ने शांति वार्ता की मेज़बानी की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के विदेश मंत्रियों के साथ चार दिनों की वार्ता की मेजबानी की। कुछ ही समय बाद, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने आर्मीनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन और अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के बीच चर्चा में मध्यस्थता की। मई के अंत में, राष्ट्रपित पुतिन ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच परिवहन लिंक को फिर से खोलने पर चर्चा के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक की मेज़बानी की हालाँकि कोई समझौता नहीं हो सका। जून 2023 के आखिर में नागोर्नो- काराबाख पर अमेरिका द्वारा शुरू की गई तीन दिवसीय वार्ता का आयोजन किया गया। हालाँकि, बातचीत के बाद प्रगति के हर बयान के बाद तनाव बढ़ गया। अज़रबैजान जब जीत के इतना करीब था तो रुकने को तैयार नहीं था। अमेरिका को भी निष्पक्ष वार्ताकार नहीं माना गया। जब अज़रबैजान का आक्रमण शुरू हुआ और उसने तेजी से नागोर्नो- काराबाख पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका, जो कूटनीतिक रूप से आर्मीनिया का समर्थन कर रहा था, इससे स्पष्ट रूप से खुश नहीं था। ब्लिंकेन से फोन पर बात करते हुए राष्ट्रपति अलियेव ने कहा कि बाकू ने आर्मीनिया को अमेरिकी समर्थन पर ध्यान दिया है जिससे संबंध खतरे में पड़ गए हैं। उन्होंने संसदीय सुनवाई में सहायक राष्ट्र सचिव जेम्स ओ'ब्रायन के बयान पर भी ध्यान दिया कि आक्रमण के बाद अज़रबैजान के साथ "हमेशा की तरह कोई व्यवसाय नहीं रहा"।

दक्षिण कौकसस क्षेत्र में प्रमुख ताकतों के हितों, इरादों और उद्देश्यों के बारे में विश्वास की कमी ने क्षेत्र में स्थायी शांति संभावनाओं को प्रभावित किया है।

घरेलू चिंताएं भी शांति की संभावनाओं का कारक हैं। साल 2020 के युद्धविराम के बाद पशिनियन को क्षेत्र के नुकासन को लेकर जबरदस्त विरोध और आर्मीनिया की सेना के साथ गतिरोध का सामना करना पड़ा। साल 2023 के युद्ध के बाद प्रदर्शनकारी येरेवन में सड़कों पर उतर आए, उन्होंने सरकार पर जातीय आर्मीनियाई लोगों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और पशिनियन के इस्तीफे की मांग की। इसका मतलब यह है कि अगर आर्मीनिया में नेतृत्व और सरकार में बदलाव होता है तो तनाव बना रह सकता है और भविष्य में भी जारी रह सकता है। स्थिति बदल भी सकती है अगर भविष्य में आर्मीनिया को भू- राजनीतिक माहौल अनुकूल लगे और वह पर्याप्त सैन्य ताकल हासिल कर ले।

2023 में आखिरी युद्ध के बाद, पशिनियन ने कहा कि उनकी सरकार पूरे नागोर्नो- काराब़ाख क्षेत्र को अज़रबैजान के संप्रभु क्षेत्र के रूप में मान्यता देती है। बदले में, उन्होंने अज़रबैजान से आर्मीनिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय सीमाओं को स्वीकार करने और नागोर्नो- काराब़ाख में रहने वाले जातीय आर्मीनियाई लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी देने का आह्वान किया। क्षेत्र पर पशिनियन की रियायत के बावजूद, दोनों पक्ष अभी भी अपनी साझा सीमा और परिवहन मार्गों के सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर असहमत हैं।
इस प्रकार, स्थिति अस्थिर बनी हुई है। क्षेत्र की स्थिरता बाहरी ताकतों की भूमिका पर भी निर्भर करती है। चुनौती मौजूदा युद्धविराम को बनाए रखने और स्थायी शांति की दिशा में काम करने की है। शांति- निर्माण के लिए बाहरी ताकतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

रूस, ईरान और तुर्की दोनों के करीब दक्षिण कौकसस में शांति और स्थिरता लाने के लिए कुछ सामान्य आधार ढूंढ़ सकता है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान ईरान और तुर्की ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठा सकते जिससे रूस मुश्किल स्थिति में आ जाए। पश्चिम द्वारा पहले से ही अलग- थलग पड़े ईरान को हमेशा रूस का समर्थन मिलता रहा है। तुर्की ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की मेज़बानी की है और भविष्य में भी ऐसा करने की पेशकश की है। अंकारा अज़रबैजान द्वारा हाल ही में हासिल किए गए लाभ से खुश है और

वह चाहेगा कि रूस उस वार्ता के लिए प्रतिबद्ध रहे जो मॉस्को ने पिछले युद्ध को समाप्त करने के लिए की थी। हालाँकि, ईरान आर्मीनिया के पक्ष में है, तेहरान की भागीदारी पर पश्चिम की प्रतिक्रिया से विवश होगा।

इसका मतलब यह नहीं है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर विचार नहीं करेंगे। अज़रबैजान तुर्की के सैन्य समर्थन से अपने हितों की रक्षा करेगा।
आर्मीनिया, ईरान से मदद पाने के अलावा, फ्रांस और भारत से सैन्य उपकरण खरीदना चाहता है। हालाँकि, नई दिल्ली इस क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए कुछ नहीं करेगी, जो युद्धग्रस्त यूक्रेन और विभाजित जॉर्जिया के पड़ोस में है लेकिन इसमें ज्यादातर पश्चिम के देश ही मायने रखेंगे। यदि पश्चिम के देश हस्तक्षेप करते हैं तो वर्तमान शांति अल्पकालिक होने की संभावना है। दूसरी ओर, यदि पश्चिमी ताकतें वर्तमान यथास्थिति और अज़रबैजान के फायदे के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहमत होती हैं, तो शांति कायम होने का मौका है। अज़रबैजान को 2022 से नागोर्नो- काराबाख में अपने घर छोड़ने वाले आर्मीनियाई लोगों को वापस लाने की अनुमति देने के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है। आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों को यह देखना चाहिए कि उनके गणराज्य धीरे- धीरे जातीय रूप से अलग हो जाएं और शांति कायम रहने पर ऐसा हो सकता है। साथ ही सामंजस्यपूर्ण अंतर-जातीय संबंध स्थायी शांति में योगदान करेंगे।

प्रो. संजय के पांडेय

धन्यवाद राजदूत विजय ठाकुर सिंह। दक्षिण कौकसस में समस्या सोवियत विघटन के बहुत पहले, 1988 के बाकू दंगों के साथ ही शुरू हो गई थी। वास्तव में, सोवियत संघ और उसकी राष्ट्रीयता नीति के लिए पहली बड़ी चुनौती तब सामने आई जब दिसंबर 1986 में तत्कालीन अल्मा- अता में जातीय हिंसा हुई। कज़ाख कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव, दीनमुखमेद कुनेव के स्थान पर जातीय रूसी कोलबिन को बनाए जाने से कज़ाख लोग नाराज थे। रूस विरोधी दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। यह एक चेतावनी थी, लेकिन इसकी प्रकृति बहुत अलग थी। यह एक जातीय दंगा अधिक था।

नागोर्नो- काराबाख युद्ध कमज़ोर पड़ा और कुछ मायनों में, संघ गणराज्यों, स्वायत्त गणराज्यों, स्वायत्त क्षेत्रों और अन्य के साथ सोवियत संघ को राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित करने की सोवियत परियोजना के सामने आने की शुरुआत हुई।

आर्मीनिया के साथ किसी भी सीमा के बिना अज़रबैजान क्षेत्र पर बहुसंख्यक आर्मीनियाई लोगों के साथ नागोर्नो- काराबाख का निर्माण एक बहुत ही गलत फैसला था। और यही मूल कारण रहा है। नागोर्नो- काराबाख आर्मीनियाई लोग सोवियत काल के दौरान पुनर्गठन और नागोर्नो- काराबाख को आर्मीनिया में शामिल करने की मांग कर रहे थे। लेकिन वह इतिहास है।

जातीय अलगाववाद की शुरुआत का पता 1988 अज़रबैजानियों और आर्मीनियाई लोगों के बीच हुई हिंसा से लगाया जा सकता है। इसके बाद तीन बाल्टिक गणराज्यों- लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और यूक्रेन एवं मोल्दोवा में भी राष्ट्रवादी दावे की मांग उठी। सोवियत विघटन के बाद 1992 से 1994 के बीच अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच विवाद स्पष्ट रूप से सामने आ गया। 1994 के युद्धविराम समझौते के साथ, नागोर्नो- काराबाख व्यावहारिक रूप से अज़रबैजान से अलग हो गया और इतना ही नहीं, उन्होंने नागोर्नो- काराबाख और मुख्य भूमि आर्मीनिया के बीच एक लिंक स्थापित करने के लिए आसपास के ई अन्य क्षेत्रों और लाचिन गलियारे पर कब्जा कर लिया। तकनीकी तौर पर युद्धविराम समझौता मई 1994 से सितंबर 2020 तक लागू रहा, लेकिन असल में झड़पें नियमित आधार पर होती रहीं।

संयोग से 1994 इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बाकू में तथाकथित 'सदी का सौदा' नाम के मेगा तेल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद तेल संपदा पर आधारित एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अज़रबैजान का उदय हुआ और आर्थिक समृद्धि के कारण अज़रबैजानी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। दक्षिण कौकसस के तीन देसों ने बहुत अलग- अलग रास्ते अपनाए: पहला था जॉर्जिया, जिसने नाटो और यूरोपीय संघ में प्रवेश पाने की उम्मीद में अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने की कोशिश की; दूसरा था- आर्मीनिया, जिसने एक और अमेरिका- यूरोपीय संघ और दूसरी ओर रूस के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की; और फिर तीसरा था अज़रबैजान, जो अपनी तेल संपदा की मदद से, एक राष्ट्रवादी दावे को बढ़ावा दे रहा था, जो आखिरकार 2020 और सितंबर 2023 के नतीजों में परिलक्षित हुआ।

अस्सी के दशक के आखिर में हमने इतिहास के अंत के बारे में सुना और 1990 के दशक के आरंभ में हमने सभ्यताओं के टकराव के बारे में पढ़ा। लेकिन हंटिंगटन के सूत्रीकरण की आलोचना करने वालों में से कुछ ने दक्षिण कौकसस को एक ऐसे मामले के रूप में बताया जिसने उनके दावे को खारिज कर दिया। यह बताया गया है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान बड़े पैमाने पर मुस्लिम बहुसंख्यक अज़रबैजान के खिलाफ ईसाई आर्मीनिया का समर्थक कर रहा है। संयोग से, यह पूरी तरह से निंदनीय या भू- राजनीतिक घटना नहीं है। ईरान में आप आर्मीनियाई चर्चों को देख सकते हैं और ऐतिहासिक रूप से आर्मीनिया के लोगों ने ईरान में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का आनंद लिया है। तो, यह सोवियत के बाद की घटना नहीं है जहां ईरान आर्मीनिया की मदद कर रहा है। कई अन्य आईआर सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, जिन्हें दक्षिण कौकसस में परीक्षण के लिए रखा गया है, उदाहरण के लिए- सभ्यताओं के टकराव के अलावा शक्ति संतुलन, सत्ता की राजनीति।

ईरान और अज़रबैजान के बारे में बात करते समय यह तथ्य याद आता है कि आज़ादी के समय अफगानिस्तान में ताजिकिस्तान की तुलना में अधिक ताज़िक हुआ करते थे (अब शायद संख्या उतनी ही है)। लेकिन यहां तो मामला और भी अजीब था। अज़रबैजान में लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) अज़ेरिस थे और ईरान में कम- से- कम दोगुनी संख्या में थे। इससे ईरान के लिए मामला और उलझ गया है। अतीत में, ईरानियों को जातीय कुर्दों और अज़ेरियों द्वारा स्वतंत्रता/ स्वायत्तता की मांगों का सामना करना पड़ा है, और एक समय में सोवियत संघ ने भी इन मांगों का समर्थन किया था। इसलिए, 1940 के दशक के दौरान अज़ेरी क्षेत्रों समेत स्वायत्तता की मांगें और आंदोलन हुए। इसलिए, ईरान की कुछ आशंकाएं समझ में आती हैं।

दक्षिण कौकसस में बहुत अजीब भू- राजनीतिक खेल चल रहे हैं। कई क्षेत्रीय या वैश्विक ताकतें ऐसा रुख अपना रही हैं जो बहुत दिलचस्प और कभी- कभी विरोधाभासी हैं। यदि हम अज़रबैजान और आर्मीनिया का मामला लेते हैं तो हमने पहले वक्ताओं को यह बात करते हुए सुना है कि भारत किस प्रकार आर्मीनिया के बचाव में आया है, हालाँकि ऐसा नहीं है।

दूसरी ओर, अज़रबैजान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता इज़रायल है। बेशक, इसने अज़रबैजान की सरकार को ओआईसी और अन्य मंचों पर हमास का समर्थन करते हुए गाज़ा युद्ध पर एक सूक्ष्म और संतुलित रुख अपनाने से नहीं रोका। तो, स्थिति वास्तव में जटिल है। संयोगवश, इज़रायल दक्षिण कौकसस का कोई नया खिलाड़ी नहीं है। अज़रबैजान और ईरान के बीच जटिल संबंधों और आर्मीनिया के प्रति ईरान के कथित झुकाव का लाभ उठाते हुए, वे काफी समय से वहाँ हैं। इज़रायली उम्मीद कर रहे हैं कि अज़रबैजान के रास्ते वे शायद ईरान पर जासूस कर सकते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।

इस प्रकार, दक्षिण कौकसस एक बहुत ही अजीब स्थिति बयां करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ईसाई आर्मीनिया का समर्थन कर रहा है जबकि इज़रायल मुस्लिम बहुल अज़रबैजान का समर्थन करता है। ईरानी अज़रबैजान को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और हाल ही में एक बहुत ही स्पष्ट स्थिति के साथ सामने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा नागोर्नो- काराबाख पर अज़रबैजान के दावे का समर्थन किया है लेकिन इसके अलावा वे किसी अन्य क्षेत्रीय दावे या पुनर्समायोजन के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान अज़रबैजान को नखिचेवन एक्सक्लेव से जोड़ने के लिए आर्मीनिया के दक्षिणी स्युनिक प्रांत के रास्ते 'ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर' बनाए जाने की योजना का विरोध कर रहा है। उनके पास ईरानी क्षेत्र के रास्ते एक गलियारा प्रदान करने की अपनी वैकल्पिक योजना है जो उन्हें पारगमन शुल्क या अन्य वित्तीय लाभ अर्जित करने में मदद करेगी और उन्हें अज़रबैजान पर लाभप्रद स्थिति प्रदान करेगी। किसी भी स्थिति में, वे 'एक राष्ट्र दो राज्य' का दावा करने वाले तुर्की और पाकिस्तान के साथ अज़रबैजान के घनिष्ट संबंधों को लेकर सहज नहीं हैं। पाकिस्तानियों को तुर्की या अज़रबैजान (तीन भाई) की यात्रा के लिए किसी प्रकार वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है।

हालाँकि, समस्या यह है कि भारत अज़रबैजान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, जिसके साथ हमारे गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। अताशगाह, ज्वाला मंदिर, गुरुमुखी और संस्कृत शिलालेख इसके कुछ उदाहरण हैं, गुरुमुखी और संस्कृत शिलालेख, त्रिशूल और कारवां सराय।

अज़रबैजान में भारत की सॉफ्ट पावर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अज़रबैजान में एक भारतीय को अच्छा महसूस होता है, उसका स्वागत हिंदी सिनेमा के गाने *आ गया आ गया, हलवा वाला आ गया* गाने के किया जाता है और दुकानों या छोटे- मोट उपहार की वस्तुओं पर उसे छूट दी जाती है।

भारत द्वारा साल 2000-2002 में आईएनएसटीसी की सबसे व्यवहार्य और दीर्घकालिक कनेक्टिविटी पहल के लिए अज़रबैजान महत्वपूर्ण है। ईरानी रश्त-अस्तारा रेलवे का निर्माण कर रहे हैं (संयोग से, अस्तारा, ईरान- अज़रबैजान सीमा के दोनों ओर है)। एक बार जब यह 167-65-किलोमीटर लंबा लिंक बन कर तैयार हो जाएगा, तो इससे आईएनएसटीसी के रास्ते यातायात में काफी सुविधा होगी। अज़रबैजान दक्षिण कौकसस में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में भारत के लिए चुनौती ये है कि दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। कलकत्ता और चेन्नई, मुंबई और अन्य जगहों पर हमारे आर्मीनियाई प्रवासी थे लेकिन हमारे पास बाकू में भारतीय कारवां सराय भी थे, बहुत सद्भावनापूर्ण और आईएनएसटीसी। तो, यह एक अजीब स्थिति है।

ईरान भी चिंतित है क्योंकि अगर यह संभावित गलियारा, आर्मीनिया के रास्ते नखचिवन को अज़रबैजान से जोड़ता है तो यह उत्तर में आर्मीनिया के रास्ते और जॉर्जिया एवं बटुमी के रास्ते भूमध्यसागरीय और यूरोप के साथ उनके स्वयं के लिंक को बाधित करेगा। बाहरी दुनिया से जुड़ने और क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए ईरान आर्मीनिया के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। शायद यही वजह है कि अज़रबैजान खुद को नखचिवन से जोड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई का सहारा नहीं ले रहा है। इसलिए, आर्मीनिया कई कारणों से ईरान के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ही भारत के लिए अज़रबैजान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हमें संतुलन बनाना होगा जिसका अभ्यास आर्मीनिया के लोग भी कर रहे हैं। ईरान एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहेगा।

चीन जिस मध्य गलियारे का निर्माण कर रहा है, उससे मध्य क्षेत्र में रुचि पैदा हुई है। चीनियों ने जॉर्जिया में निवेश किया है लेकिन अज़रबैजान में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है, इस तथ्य के बावजूद कि अज़रबैजान भी पश्चिमी कनेक्टिविटी पहल का हिस्सा है। जहाँ तक सबसे पहले इस क्षेत्र में भारत के लिए चीन की उपस्थिति के निहितार्थ का सवाल है,

इनमें से किसी भी देश के साथ हमारा कोई बड़ा व्यापार नहीं है।

मध्य एशिया में, जो हमारे विस्तारित पड़ोस में मुख्य में दिलचस्पी का मुख्य विषय है, चीनी व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी में भारी उपस्थिति रखते हैं। इसी तरह, चीन के दक्षिण कौकसस देशों के साथ बहुत ठोस व्यापारिक संबंध हैं, और रहेंगे।

धन्यवाद, राजदूत अचल मल्होत्रा, राजदूत विजय ठाकुर सिंह। और हमने अभी- अभी प्रतिष्ठित पैनल को ऐतिहासिक और भू- राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए सुना। प्रो. पांडेय ने बहुत ही उचित तरीके से ज्ञानात्मक संबंधों, पृष्ठभूमियों और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बताया और हंटिंगटन के सभ्यतागत टकराव के सिद्धांत की निंदा की।

प्रो. अख़लाक अहमद

मैं पूरे मध्य एशियाई देशों के अलावा इस पूरे क्षेत्र को पूर्व यूएसएसआर के विभाजन और मुख्य रूप से कौकसस या मध्य एशियाई देशों में जातीय पहचान के आधार पर इन देशों के निर्माण के बाद अपनी पहचान के भ्रम में संघर्ष करते हुए देखता हूँ (जैसा कि प्रोफेसर पटनायक ने भी कहा था); इनकी ऐतिहासिक और जातीय- उप- राष्ट्रवादी पहचानें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें क्षेत्र के विभिन्न देशों में समान जातीय पहचान बिखरी हुई मिलती है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कज़ाकिस्तान से कुछ छात्र आए थे और उन्होंने बताया कि उन्हें भी समरकंद बहुत पसंद है क्योंकि उनका राष्ट्रीय नायक तैमूर वहीं से है। तो, मैंने पूछा कि क्या तैमूर आपका भी राष्ट्रीय नायक है?
उन्होंने कहा, हाँ, और उसे कज़ाख नायक कहा। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था कि वह केवल उज़्बेकिस्तान और उज़्बेक लोगों का राष्ट्रीय नायक है। इसलिए, बहुत सारी अंतर- मिश्रित सांस्कृतिक जातीय पहचानें हैं। उदाहरण के लिए यदि आप ताजिकों से पूछें तो वे बुखारा, समरकंद, शाहरिसबज़ को अपना सांस्कृतिक क्षेत्र बताएंगे।

इसलिए, मुझे एक अलग पहलू के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ भू- राजनीतिक भाग पर विस्तार से चर्चा की गई है और इसकी सभी विशेषताओं पर चर्चा की गई है, मैं इतिहास, सांस्कृतिक और उन मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जो न केवल

अज़रबैजान को बल्कि हमारी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ता है। उदाहरण के लिए, फ़ारसी और अन्य भाषाओं समेत हमारी संपूर्ण शास्त्रीय साहित्यिक परंपरा में हम इस क्षेत्र को कौकसस के रूप में पहचानते हैं, जो किंवदंतियों और रोमांटिक कल्पनाओं से भरा है। और यह फ़ारसी साहित्य का हिस्सा रहा है, जो पिछली कई शताब्दियों से उपमहाद्वीप में एक भारतीय भाषा के रूप में प्रचलित है, हमारी अपनी अन्य भारतीय साहित्यिक परंपराओं के अलावा, उदाहरण के लिए कोहे- काफ़ की परियां (कौकसस की परीकथाएँ) का संदर्भ। *दास्तान ए अलिफ़ लैला* या *अ थाउजेंड नाइट्स* या *बाग- ओ- बहार* जैसी कहानियों में अमीर खुसरो की कहानी *चाहर दरवेश* का अनुवाद फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया था और इसी तरह की कई कहानियाँ, किंवदंतियाँ और किस्से हैं।

जब भी मैं अताशगाह जाता हूँ, मुझे इससे जुड़ी किंवदंतियां और इतिहास याद आ जाता है। अताशगाह जो बाकू में है, जरथुस्त्र का जन्मस्थान भी है। वहाँ से वे चले गए और पूरे ईरान की यात्रा की और समकालीन बल्ख में आए जो अब अफगानिस्तान में है और वहां वे एक नई धार्मिक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में सफल हुए। वहाँ से, बहुत बाद में, और उसके बाद कई शताब्दियों के बाद, यह ईरान और मध्य एशिया का आधिकारिक धर्म बन गया। तो, अज़रबैजान और उसके सौंदर्यशास्त्र की यह पूरी कहानी हमारी कल्पना का हिस्सा इस कारण से भी है क्योंकि यह रेशम मार्ग (सिल्क रूट) पर है और भारतीय व्यापारी समरकंद, बुखारा, मध्य एशिया के साथ- साथ ईरान और इस कौकसस क्षेत्र का दौरा किया करते थे। यहां तक कि मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के काल में भी, हम भारत, आर्मीनिया और रोमनों के बीच संबंध पाते हैं क्योंकि उनकी एक उपपत्नी आर्मीनिया से थी और बहुत बाद में, हम पाते हैं कि सम्राट अकबर की पत्नियों में से एक भी आर्मीनिया से थी। और भारत में अर्मीनिया के लोगों के साथ- साथ अज़ेरी के लोगों की बस्तियाँ भी कई शताब्दियों से हैं, यहाँ तक कि तुर्कों के आने और इस क्षेत्र पर शासन शुरू करने से भी बहुत पहले से।

इसी तरह, अज़रबैजान की कुछ महानतम हस्तियों का हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

उदाहरण के लिए, अज़रबैजान के पश्चिमी भाग में एक जगह है, जिसे गांजा कहा जाता है। एक महान कवि हुए जो अब अज़ेरिस और अज़रबैजान के राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतीक भी हैं, गांजा के निज़ामी। निज़ामी फ़ारसी भाषा के महान कवि होने के साथ- साथ ईरान और भारत की फ़ारसी परंपरा में भी उतने ही प्रतिष्ठित हैं। और मैं फ़ारसी परंपरा का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगभग 1,000 वर्षों से, फ़ारसी परंपरा ने हमारी अपनी भारतीय सभ्यता और परंपराओं को प्रभावित किया है। सारा साहित्य या भाषाएं जिन्हें हम आज आधुनिक भारतीय भाषाएँ कहते हैं, वे अपनी स्थानीय बोलियों, संस्कृत और फ़ारसी के सीधे प्रभाव में रही हैं।

इसलिए, निज़ामी ने खमसा की रचना करके संपूर्ण शब्दावली और साहित्यिक परिदृश्य को बदल दिया जो ईरानी पुनरुत्थानवादी आंदोलन से निकला था और जिसकी कुछ कट्टरपंथी शैली थी और इसे दार्शनिक, रहस्यवादी और रोमांटिक विषयवस्तु की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल एक विनम्र और अधिक साहित्यिक शब्दावली में बदल दिया। इस प्रकार एक नई विचारधारा की शुरूआत की।
निज़ामी के बाद वहाँ से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक 200 से अधिक कवियों ने खमसा की नकल और पुनरुत्पादन करने की कोशिश की और उनमें से सबसे सफल अमीर खुसरो रहे। इस खमसा परंपरा ने बाद में हमारी अपनी भक्ति, हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि कविताओं की सूफी परंपराओं को प्रभावित किया जिनमें उदाहरण के लिए जायसी, कुतबन, रांझन और चैतन्य आदि शामिल हैं।

इसलिए, अगर आप टैगोर की कविता को भी पढ़ेंगें तो उनकी कविता निज़ामी और उनके जैसे कवियों से प्रभावित पाएंगे। और जब मैंने पहली बार 2017 में एकेडमी ऑफ साइंसेसज, बाकू का दौरा किया और भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना में मदद की, तब अज़रबैजान में टैगोर की लोकप्रियता और भारत एवं भारतीय परंपराओं के प्रति स्नेह देखा है। उनकी एक संकाय सदस्य ने अपने शोधकार्य के लिए भारत- अज़ेरी सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए मेरी मदद भी ली। और हाल ही में पिछले साल मैंने फिर से उसी भारतीय केंद्र का दौरा किया, जो अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। इसलिए, मुझे लगता है, इन सांस्कृतिक संबंधों को, कोमल हिस्सों को भी पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

रेशम मार्ग (सिल्क रूट) से लेकर कहानियों और साहित्य तक हमारे बीच बहुत व्यापक और विशाल संबंध हैं और यह आज भी बने हुए हैं।

हाल ही में उन्होंने टैगोर के आठ खंडों का अनुवाद किया है, जिन्हें शिक्षाविद् प्रोफेसर ईसा हबीबली के कुशल नेतृत्व में विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया था और टैगोर पर एक पुस्तक प्रोफेसर बदीर खान द्वार लिखी गई है। इसलिए, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान और तुर्की जैसे देशों के बीच जटिल संबंधों के बावजूद ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। ईरान और अज़रबैजान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, उन्हें यात्रा के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, बहुत सारे लोग, विशेष रूप से ईरान निवासी अज़रबैजान का दौरा कर रहे हैं और यह निश्चित रूप से लोगों के बीच संबंदों को मजबूत करने में एक भूमिका निभाता है।

इसलिए, ये सांस्कृतिक, भाषाई संबंध और पहलू अधिक शक्तिशाली घटक हैं और यूरोपीय देशों के विपरीत, इन देशों को अभी भी विभिन्न पहचानों के प्रति उदार होना सीखना बाकी है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से किसी भी देश या दुनिया के किसी भी हिस्से की केवल एक ही पहचान नहीं हो सकती है। इसलिए, उन्हें उदार होना होगा और उन्हें सीखना होगा कि सभी क्षेत्रों, सभी देशों और राष्ट्रीयताओं का संस्कृतियों, भाषाओं और साहित्य की विभिन्न धाराओं के साथ संबंध और संयोजन है।

राजदूत अचल मल्होत्रा

प्रोफेसर अख़लाक, भारत और दक्षिण कौकसस तथा ईरान जैसे देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों पर आपने बहुत ज्ञानवर्धन किया, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जब हम विश्व के इस हिस्से के साथ संबंध बनाने को उत्सुक हैं तब, इन संपर्कों को पुनर्जीवित किए जाने की आपकी अनुशंसा विचार करने लायक है। मैं दुनिया के उस हिस्से में भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देने में आपके व्यक्तिगत योगदान की भी सराहना करता हूँ। एक बार फिर आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

अच्छी बात है। देवियों और सज्जनों, अब आप सब अपने प्रश्न पूछ सकते हैं एवं हमारे पैनल के विशेषज्ञ आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।

राजदूत अचल मल्होत्रा

मेरा अनुरोध है कि कृपया संक्षिप्त उत्तर पूछें, लंबी टिप्पणी करने की बजाए प्रश्न पूछें ताकि अधिक- से- अधिक लोगों को प्रश्न पूछने का मौका मिल सके। धन्यवाद।

डॉ. अमिताभ सिंह

यह बहुत ज्ञानवर्धक सत्र था और मैं 15 वर्षों के बाद यहाँ वापस आया हूँ। मैं आईसीडब्ल्यूए शोधकर्ताओं के पहले बैच का सदस्य था जिसने आईसीडब्ल्यूए उस समय ज्वाइन किया था जब आईसीडब्ल्यूए सप्रू हाउस पुस्तकालय से अधिक बन चुका था। लेकिन मैं वहां केवल 2 माह तक ही रह सका क्योंकि अध्यापन और शोध एक साथ नहीं किए जा सकते थे क्योंकि मुझे यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहना होता था। इस क्षेत्र पर मेरी संक्षिप्त टिप्पणी।

मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन जिस देश से भारत को सावधान रहने की जरूरत है वह है आर्मीनिया। क्यों? इसके दो- तीन कारण हैं। हम सभी ने प्रतिक्रिया दी है, आईएनएसटीसी (INSTC) पर बात की है लेकिन आईएनएसटीसी (INSTC) अज़रबैजान के रास्ते रूस और उससे भी आगे, मेरा मतलब है सेंट पीटर्सबर्ग तक, जाने के बारे में है। वैकल्पिक मार्ग ईरान, आर्मीनिया, जॉर्जिया से काला सागर और फिर आगे यूरोप भी हो सकता है। क्योंकि यह संचार का युग है और हमने हाल ही देखा है कि हूती विद्रोहियों ने स्वेज नहर के रास्ते में हमला कर उस रास्ते को रोक दिया है। इसलिए, वैकल्पिक मार्ग तलाशने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि आर्मीनिया और पाकिस्तान, उदाहरण के लिए, वे दोनों एक दूसरे को राष्ट्र नहीं मानते। न तो आर्मीनिया पाकिस्तान को एक देश मानता है और न ही पाकिस्तान आर्मीनिया को। पिछले कुछ वर्षों में आर्मीनिया की भारत में पहुँच बहुत बढ़ी है। रायसीना वार्ता में उनका बड़ा दल था। और हम उनके साथ रक्षा उपकरणों का व्यापार कर रहे हैं जो दिनों- दिन बढ़ रहा है। आज केवल अज़रबैजान ने ही करीब 64 जेएफ- 17 (JF-17) विमानों का ऑर्डर दिया है जिसे पाकिस्तान और चीन मिल कर बनाया है। इसलिए वे 1.4 अरब (1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे की प्रक्रिया में हैं।

और साथ ही, भारत के लिए नीतिगत निहितार्थ के संदर्भ में, यह होगा कि हम आर्मीनियाई नरसंहार को मान्यता देने के बारे में सोचना शुरू करें जो विश्व के लगभग 30 देशों ने किया है। भारत ने ऐसा नहीं किया है और यह उन लोगों के खिलाफ़ बचाव का काम करेगा जिन्हें

वे तीन भाई कहते हैं- तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान। ग्रीस के मामले में हम पहले ही उनसे दोस्ती कर चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री को ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। जब तुर्की और अज़रबैजान के खिलाफ बचाव की बात आती है तो हम आर्मीनिया के साथ भी इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि कश्मीर पर तुर्की का रुख जगजाहिर है। अज़रबैजान भी मोटे तौर पर इससे सहमत है और पाकिस्तान पहले से ही वहाँ मौजूद है।

तो, इस तुर्की या नव- तुर्कवाद के खिलाफ एक बचाव के रूप में, जो आकार ले रहा है, और अंत में, आर्मीनिया और भारत, ऐतिहासिक रूप से, एक पौराणिक कथा है, जिससे आर्मीनियाई भी खुद को जुड़ा मानते हैं। 349 ईस्वी से पहले, जब आर्मीनिया विश्व का पहला ईसाई साम्राज्य बना, तो हमारे एक, दो भारतीय हिन्दू भाई थे, जो आर्मीनिया गए और उन पर शासन किया, है ना? तो, यह इतिहास और पौराणिक कथाओं में है। मैं हिंदू पक्ष पर ज़ोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, हमारे बीच जो संबंध था....

राजदूत अचल मल्होत्रा

उस समय हिंदू भारत में ही थे।

डॉ. अमिताभ सिंह

मेरे कहने का मतलब है कि वे केवल इन हिन्दुओं से हार गए थे जो वहाँ गए थे, उन दो भाईयों से। लेकिन समय के साथ, जब ईसाई धर्म हावी हो गया, तो वे इसका हिस्सा बन गए- लेकिन उन्होंने अपना इतिहास इन भारतीय लोगों से खोजा। अब आखिरकार, मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि अज़रबैजान को तुर्की के मोर्चे पर सावधान रहने की जरूरत है, यह ज़ंगेज़ुर गलियारा एक बड़ा गेम चेंजर होगा। आर्मीनिया के लोगों को जिस अगली बात का डर है, वह यह है कि अज़रबैजान को नागोर्नो-काराबाख पर कब्ज़ा करने के लिए 21 दिनों की तैयारी करनी पड़ी। और उन्होंने वह कर दिखाया, जो वे 30 वर्षों में नहीं कर सके। कार्रवाई का अगला चरण ज़ंगेज़ुर कॉरिडोर के लिए हो सकता है और यह कैस्पियन सागर, अज़रबैजान को नखचिवन, तुर्की से होते हुए काला सागर तक जोड़ेगा। और इससे पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप, ईरान, को क्षेत्र के उस हिस्से से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए, यह भी जरूरी है, मेरा कहने का मतलब है कि हमारी सीमाओं के करीब आने वाले इस नए तुर्कवाद को रोकने के लिए भारत को इस उपाय में सक्रिए रूप से शामिल होने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

राजदूत अचल मल्होत्रा

धन्यवाद।

डॉ. संजीव कुमार

धन्यवाद महोदय। आइए मैं इस चर्चा में चीन को शामिल कर लेता हूँ। कुछ महीने पहले, चीन ने जॉर्जिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की थी और क्या जॉर्जिया ने चीन के सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार कर लिया था, जिसमें ताइवान, बीआरआई (BRI) और सभी नई विकास पहलों, वैश्विक पहलों और सभ्यतागत पहलों पर चीन की स्थिति की मांग शामिल थी। तो, मेरा प्रश्न यह है कि चीन- जॉर्जिया रणनीतिक साझेदारी किस तरह से क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित करने वाले हैं और यह भी क्या जॉर्जिया के साथ भारत की स्थिति से इसका कोई संबंध है? धन्यवाद।

प्रो. संजय पांडेय

ईमानदारी से कहूँ तो, चीन के मामले में मुझे नवीनतम जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से, यह संपूर्ण मध्य गलियारा जिसका निर्माण चीन कर रहा है, या उस मामले में, कई मध्य एशियाई देश इसमें रुचि रखते हैं, जिसमें कज़ाकिस्तान भी शामिल है, जो पहले से ही बीटीसी पाइपलाइन के जरिए तेल भेज रहा है। इसलिए, चीनियों ने न केवल जॉर्जिया में निवेश किया है, बल्कि वे अज़रबैजान में भी बहुत गहरी रुचि रखते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि अज़रबैजान पश्चिमी कनेक्टिविटी पहल का हिस्सा है।

तो, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले, हमारा अभी भी इनमें से किसी भी देश के साथ कोई बड़ा व्यापारिक संबंध नहीं है।
संपूर्ण मध्य एशिया, जो हमारे विस्तारित पड़ोस में हमारे दिलचस्पी का मुख्य केंद्र है, वहाँ भी चीन की मौजूदगी है, बहुत बड़े पैमाने पर मौजूदगी है, चाहे बात व्यापार की हो या निवेश कि या कनेक्टिविटी की। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत बड़े पैमाने पर प्रभावित है क्योंकि चीन मध्य एशिया में है, चीन के दक्षिण कौकसस देशों के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, इसलिए इसकी उपस्थिति वहाँ बनी रहेगी। इस क्षेत्र में हमारे पास अधिक विकल्प नहीं हैं।

राजदूत अचल मल्होत्रा

यदि मैं कुछ तथ्यों को जोड़ना चाहूँ। चीन ने इस क्षेत्र से कोई 10 साल पहले ही संबंध बनाने शुरू किए हैं और उनकी बीआरआई (BRI) परियोजनाएं इस क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकार की गई हैं। प्रथम दृष्टया, चीन इस समय कनेक्टिविटी, आर्थिक पैठ में अधिक दिलचस्पी रखता है, और मुझे नहीं लगता कि जिस दिशा में इस क्षेत्र को आगे बढ़ना चाहिए उसे प्रभावित करने, आकार देने में उनकी कोई बड़ी भूमिका निभाने की कोई योजना नहीं है।

भारत के लिए, यह एक और ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम अपनी विदेश नीति में चीन के कारक को शामिल करना होगा। और चीन के संदर्भ में, हमने मोटे तौर पर पहले से ही तीन या चार सी (अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर- C) की नीति अपनाई हुई है जिसका अर्थ है- संभव हो तो सहयोग (कोऑपरेट- cooperate) करें, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो प्रतिस्पर्धा (कंपीट- compete) करें, प्रतियोगिता (कॉन्टेस्ट- contest) और चुनौती (चैलेंज- challenge)। तो यह एक और दूसरे सी(C), यानी चीन, के साथ कई सारे सी (C) का मिश्रण है, हमने इसे अपनाया है और मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस क्षेत्र में भी यही नीति अपनाएंगे।

प्रो. संजय पांडे

वास्तव में, भू-राजनीतिक दृष्टि से, चीनियों ने इस क्षेत्र को रूसियों के लिए छोड़ दिया है। उनका मानना है कि यह रूस के महत्वपूर्ण हित का क्षेत्र है, जहाँ रूस बड़े पैमाने पर शामिल है, जिसमें नागोर्नो- काराब़ाख भी शामिल है, अब और नहीं, मुझे डर है। और इसलिए, वे इससे निपटने के लिए इसे रूस पर छोड़ देंगे।

प्रो. अजय पटनायक

केवल एक वाक्य। रूस ने मान लिया है कि वह बीआरआई (BRI) का हिस्सा बनेगा। इसलिए, कोई भी पूर्व- पश्चिम कनेक्टिविटी जो चीन, रूस और भू-मध्य सागर को तुर्की से जोड़ती है, रूस उसका स्वागत कर रहा है।

डॉ. लक्ष्मी प्रिया

मेरा प्रश्न है, ईरान, हम जानते हैं कि यह इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम चर्चा करते रहे हैं। तो क्या हमें ईरान को आर्मीनिया- अज़रबैजान समीकरण में एक संतुलनकर्ता या सक्रिए खिलाड़ी के रूप में देखना चाहिए? धन्यवाद।

श्रोता

नमस्कार। पैनल के कोई भी विशेषज्ञ मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अनाधिकारिक रूप से, मैं सहमत हूँ लेकिन आपको क्या लगता है- रणनीतिक संबंधों की जो चर्चा चल रही है वह क्या है? आर्मीनिया और भारत के बीच बातचीत चल रही है और मेरा मानना है कि आर्मीनिया के उप विदेश मंत्री भी हाल ही में भारत के दौरे पर थे और भारत के साथ रणनीतिक संबंध बनाने, इस संबंध को रणनीतिक स्तर तक ले जाने के संबंध में बहुत सक्रिए सार्वजनिक घोषणाएं भी की गईं। और आप उनके द्वारा किए जा रहे थोड़े- बहुत प्रयास के अलावा भारत के योगदान को कैसे देखते हैं? और जैसा कि हर किसी ने बताया है कि दुर्भाग्य से यह एक सच्चाई है कि हम हमेशा कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और हम कनेक्ट होने वाले अंतिम लोग हैं। हमारे सभी सभ्यतागत संबंधों के बावजूद हाल ही में निजी उद्यम की बदौलत हम कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के मामले में इस क्षेत्र तक पहुँच रहे हैं और हमारे

पास अभी भी ऐसा नहीं है- मेरा मतलब है कि पूरे मध्य एशिया क्षेत्र और “ कौकसस,” पर विचार करें, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो यब बहुत ही अनियमित है।

रिधित राय

तो, मेरा सवाल यह है कि क्या भारत आर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया के साथ अपने व्यक्तिगत द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित कर सकता है?

राजदूत अचल मल्होत्रा

तो, सबसे पहले बात ईरान के बारे में। क्या ईरान संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे?

प्रो. अख़लाक अहमद

मुझे लगता है, हाँ। अज़रबैजान के साथ ईरान के सहज, असुविधाजनक संबंध हैं। लेकिन अज़रबैजान एक मज़बूरी भी है, ऐतिहासिक दृष्टि के साथ-साथ भौगोलिक दृष्टि से भी। ईरान को अज़रबैजान के साथ अच्छे संबंध रखने ही होंगे क्योंकि इसकी 40% आबादी तुर्कों की है। इनका व्यापार, सेना सब कुछ पर नियंत्रण है। इसलिए, किसी- न- किसी रूप में अज़रबैजान के साथ उनका एक तरह का रिश्ता है, हालांकि कभी- कभी यह थोड़ा अज़ीब हो जाता है।

और आर्मीनिया, हाँ, ईरान के साथ उनका बहुत गहरा ऐतिहासिक संबंध, मेरे विचार से 16वीं सदी के बाद का, है। और ऐसे में अगर अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच किसी तरह का स्थायी समझौता होने वाला है तो ईरान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रो. संजय पांडेय

ईरान भी, एक तरह से, आर्मीनिया के लिए सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यदि ऐसा कोई भी गलियारा बन जाता है तो ईरान एक ऐसा देश है जो, मेरा कहने का मतलब है कि, आर्मीनिया के अलावा, जो सबसे अधिक नुकसान में होगा और उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से बता भी दिया है। वास्तव में, यह एक कारण हो सकता है जो अज़रबैजान को नखचिवन के साथ जोड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई करने से रोकता है। तो, ईरान एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकता है और रहेगा भी। हाँ, यह एक संतुलनकर्ता देश भी हो सकता है।

राजदूत अचल मल्होत्रा

दो अन्य प्रश्न भी थे, आर्मीनिया- भारत रणनीतिक संबंध।

प्रो. अख़लाक अहमद

जी हाँ। आपका अगला सवाल आर्मीनिया- भारत रणनीतिक संबंधों के बारे में था, क्या इस प्रश्न का उत्तर मैं दूँ या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे?

राजदूत अचल मल्होत्रा

इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। मुझे लगता है कि यदि आप इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों के इतिहास को देखें तो हमें सुदूर अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं है जब 149 ईपू में वहां कुछ भारतीय बस्तियाँ थीं और फिर आर्मीनियाई प्रवासी पहले मुगल और बाद में ब्रिटिश काल के दौरान भारत में एक महत्वपूर्ण निभा रहे थे। वे अपने पीछे अपने गौरवशाली अतीत के साक्ष्य के रूप में बहुत सारे चर्च, गिरजाघर छोड़ गए हैं। इसलिए बहुत सी चीजें हैं। उनकी पहली पत्रिका यहीं से प्रकाशित हुई थी और फिर एक काल्पनिक आर्मीनियाई राष्ट्र के संविधान का मसौदा भी तैयार किया गया था। और भी बहुत सारी चीजें थीं। लेकिन भले ही आप यह भूल जाएं, अगर आप 1992 के बाद से देखें, तो भारत और आर्मीनिया के बीच राजनीतिक वार्ता का स्तर एक अलग ही मुकाम पर है। उस देश के तीन राष्ट्रपति भारत का दौरा कर चुके हैं जबकि अन्य दो देशों से कोई नहीं आया। उप-राष्ट्रपति के तीन दौरे हुए हैं और हाल ही में निश्चित रूप से इसमें तेज़ी आई है। बहुत सारी घटनाएं जुड़ रही हैं। बहुत संक्षेप में और सटीक रूप से कहें तो, मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में हर वह तत्व है जो हमारे रिश्ते को एक रणनीतिक रिश्ते में बदलने की अनुमति देना चाहता है। यह कितनी जल्द संभव है या ऐसा होने में कितना समय लग सकता है, इस समय यह बता पाना मुश्किल है।

और आपने कनेक्टिविटी के बारे में उल्लेख किया। हाँ। कनेक्टिविटी में, हमने हमेशा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है और उन्हें व्यावसायिक व्यवहार्यता देखनी होगी। हाल ही में, हम त्बिलिसी और बाकू दोनों से हवाई मार्ग से जुड़े हैं और जब मेरी वहां नियुक्ति की गई थी तब येरेवन से दिल्ली तक की सीधी उड़ान सुविधा उपलब्ध थी। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में मुझे 4 घंटों का समय लगता था। तो, इससे पता चलता है कि हम कितने करीब हैं। लेकिन फिर इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होना होगा। तो, उन्हें इसे बनाने के तरीके और साधन खोजने होंगे या तो इसे तीसरे या पांचवें स्वतंत्रता अधिकारों तक विस्तारित करना होगा या उड़ान का विस्तार करना होगा। तो, यह सब व्यावसायिक विचार है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार की भूमिका है लेकिन निजी क्षेत्र की तुलना में इसकी भूमिका सीमित है। और निजी क्षेत्र ने इसे अज़रबैजान और कई अन्य स्थानों में ऊर्जा क्षेत्र में बिना किसी देरी के-

जॉर्जिया में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया है। तो, यही तथ्य है।

प्रो. अजय पटनायक

एक और सवाल था। क्या भारत स्वयं बना सकता है, स्वयं से संतुलन स्थापित कर सकता है?

प्रो. अचल मल्होत्रा

क्या भारत स्वयं बना सकता है- प्रत्येक देश के साथ संबंध, है ना?

क्या भारत स्वयं संतुलनकर्ता बन सकता है?

प्रो. अजय पटनायक

क्या भारत आर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया के साथ अपने व्यक्तिगत द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित कर सकता है?

रिधित राय

क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे क्योंकि बाकी सभी ने उत्तर दिए हैं।

राजदूत अचल मल्होत्रा

प्रो. अजय पटनायक

देखिए, संतुलन किस अर्थ में? क्या आप चाहते हैं कि भारत सैन्य संतुलनकर्ता बने, भू- राजनीतिक संतुलनकर्ता बने, तो मुझे इसकी संभावना नज़र नहीं आती। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों के साथ संबंध हैं। चीन के साथ भी हमारा बड़ा व्यापारिक संबंध हैं। इसलिए, यदि कोई भी देश आर्थिक रूप से अलग-थलग पड़ जाता है, ठीक है, और उसे राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता है, तो भारत आ सकता है। लेकिन अंततः ये दोनों देश समाधान या जीत या हार के लिए रूस पर निर्भर होंगे।

इसलिए, आप रूस के खिलाफ संतुलन नहीं बना सकते। अगर अज़रबैजान फिर से रूस के करीब जाता है, तो यह मुश्किल होगा या आर्मीनिया रूस के साथ जाता है, तो यह मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टि से इसे बुनियादी ढांचा कहा जाता है। तो, अधिकार और विकल्प दीजिए। हम यही कर सकते हैं क्योंकि अन्यथा आर्मीनिया के पास बुनियादी ढांचे या कनेक्टिविटी के अलावा कोई संसाधन नहीं है। इसके पास कोई संसाधन नहीं है और अज़रबैजान के पास संसाधन हैं। पाकिस्तान कारक के कारण हम आज अपने विकल्प बंद नहीं कर सकते हैं और अगामी 10 वर्षों, 15 वर्षों में, हम अज़रबैजान के साथ ऊर्जा समझौते का विकल्प चुन सकते हैं।

इसलिए, यह इतना आसान नहीं है कि भारत संतुलन के लिए इसे या उसे चुनेगा।

राजदूत अचल मल्होत्रा

क्या हमें एक और प्रश्न का उत्तर देना चाहिए? यदि हाँ, तो हम देंगे।

राजदूत विजय ठाकुर सिंह

आप एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

राजदूत अचल मल्होत्रा

ठीक है। हम तीन और प्रश्नों के उत्तर देंगे।

दर्शक

धन्यवाद। जब पैनल में आपके दो पूर्व शिक्षक बैठे हों तो प्रश्न पूछना बहुत कठिन हो जाता है। मैं उसी विचारधारा के विद्यालय से प्रशिक्षित हूँ। लेकिन जब मैं ये चर्चा सुन रहा था, उसमें प्रोफेसर पटनायक ने कहा कि चीन ने इसे रूस के लिए प्रभाव क्षेत्र माना है और वर्तमान प्रकार की भू- राजनीति को देखते हुए जहाँ रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ गई है, निश्चित रूप से, हम अभी तक उनके बीच किसी भी प्रकार के विवाद को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन कैसे- क्योंकि रूस खुद को एक बड़ी शक्ति मानता है और चीन इस क्षेत्र में प्रवेश ही कर रहा है और जॉर्जिया के मामले में पहले से ही यह सवाल पूछा जा चुका है कि सहज होने में रूस को कितना समय लगेगा? और हम जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध से पहले चीन और रूस के बीच तीन मुद्दे थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा और सहज था। तो, एक महान शक्ति की महत्वाकांक्षा से, दुनिया के इस हिस्से में चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ रूस कितना सहज हो पाएगा?

डॉ. हिमानी पंत

मेरा नाम हिमानी है। मैं परिषद में शोध अध्येता हूँ। मेरे पास दो बहुत संक्षिप्त प्रश्न हैं। एक, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में व्यस्त है, हम पश्चिम और इस क्षेत्र, दक्षिण कौकसस क्षेत्र के बीच भागीदारी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो, पैनल में शामिल सदस्य पश्चिम और रूस के बीच दक्षिण कौकसस क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन कैसे करेंगे?

दूसरा है, अलग हुए क्षेत्रों के संबंध में। पिछले वर्ष अक्टूबर में, आपने देखा कि रूस ने अब्र्खज़िया के साथ काला सागर नौसैनिक अड्डे के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी जॉर्जिया की सरकार ने आलोचना की। और उसने इसे अपनी संप्रभुता के उल्लंघन की श्रेणी में रखा। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मोल्दोवा को ले लें, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने रूस से सुरक्षा की मांग की है। तो, इस संदर्भ में, आप क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाड़ी के रूप में रूस की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि प्रोफेसर पटनायक ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ। वे रूस को एक भू- राजनीतिक संतुलनकर्ता के रूप में देखते हैं लेकिन

यह देखते हुए कि काला सागर का क्षेत्र, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे अधिकांश तटीय देश भी नाटो के सदस्य हैं, आप दक्षिण कौकसस के साथ-साथ आस- पास के क्षेत्र में भी स्थिरता को किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद।

दर्शक

नागोर्नो- काराबाख की हार के बाद आर्मीनिया किस प्रकार की वैकल्पिक सुरक्षा की तलाश में है? क्या वह फिर से गारंटर के रूप में रूस की ओर कदम बढ़ा रहा है?

प्रो. अजय पटनायक

तो, देखिए, इस कमरे में बैठे सभी लोगों की तरह ही, हम भी इस बात से चिंतित हैं कि रूस कैसे चीन पर निर्भर हो जाएगा। रूस के जो नीति- निर्माता हैं, वे विचारक भी हैं, वे भी बहुत चिंतित हैं क्योंकि वे भी कल्पना कर सकते हैं। आप देखिए, यह एक बड़ा देश है और चीन के साथ उनके युद्ध का इतिहास रहा है। लेकिन कभी-कभी मैं कहता हूँ कि यह एक प्रकार का श्रम विभाजन है। आप देखिए, चीन उन क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा है जिन क्षेत्रों में रूस की क्षमता कम है जैसे अर्थव्यवस्था, पूंजी, निवेश। इसलिए, यह तब तक चिंतित नहीं होगा, बहुत अधिक चिंतित नहीं होगा, अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होगा जब तक चीन उन क्षेत्रों में कुछ भू- राजनीतिक प्रकार की भूमिका में नहीं आएगा। इसलिए, रूस को उस क्षेत्र में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और जिन क्षेत्रों में रूस कुछ नहीं कर सकता, वहाँ चीन अपना काम कर रहा है। और जब तक चीन रूस का घनिष्ठ मित्र है और ऐसा कर रहा है, तब तक रूस को चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है लेकिन रूस के पास इस क्षेत्र में बहुत अधिक अधिकार है रूस का प्रभाव भी इस क्षेत्र में बहुत व्यापक है। इसलिए किसी भी समय परिस्थिति बदलने पर वह चीन का मुकाबला कर सकता है। फिर आप जो कह रही थीं- आपने क्या कहा था?

डॉ. हिमानी पंत

भू- राजनीतिक संतुलन बनाम अन्य शक्तियों के मामले में रूस की भूमिका।

प्रो. अजय पटनायक

देखिए, पश्चिम स्वयं को इस क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है। जॉर्जिया एक संभावना थी, लेकिन 2008 में उस युद्ध के साथ, जॉर्जिया पर पश्चिम का प्रभाव कम हो गया और आप देखिए 2008 से 2024 तक, रूस के साथ जॉर्जिया के संबंधों में सुधार हुआ है और आज, मोल्दोवा और अन्य पूर्वी यूरोपीय पड़ोसियों के प्रतिबंधों और दबाव के बाद भी, जॉर्जिया ने रूस के लिए अपनी सीमाएं बंद नहीं की है। और मैंने रिपोर्टें पढ़ीं हैं जिनमें यूरोप की अधिकांश प्रयुक्त कारें, जो पहले रूस जा रही थीं,

बड़ी संख्या में, यह एक बड़ा बाज़ार है, अब वे जॉर्जिया जा रही हैं और जॉर्जिया से रूस भेजी जाती हैं। इसलिए, कई देश जॉर्जिया पर सीमा बंद करने, संपर्क काटने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन जॉर्जिया ने ऐसा नहीं किया है, जॉर्जिया 2008 के उन दिनों से दूर चला गया है जब राष्ट्रवादियों ने देश पर शासन किया था और अब उन पर जॉर्जिया के दो महत्वपूर्ण हिस्सों को गंवाने का आरोप लगाया जा रहा है।

पशिन्यान के साथ भी यही हो रहा है। ऐसा करने की बजाय, इसे कूटनीतिक तरीके से निपटने के कारण, अब उसे इन क्षेत्रों को वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। इसलिए, कई देशों को ऐसा लग रहा है कि रूस को नाराज़ करने से, उसे खतरा महसूस कराने से उनकी स्थिरता नहीं बनेगी। कज़ाकिस्तान आज स्थिर क्यों हैं? मध्य एशिया क्यों है? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे रूस को ख़तरा महसूस हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे रूस असुरक्षित महसूस करे। तो, मध्य एशियाई छोटे हो सकते हैं। कज़ाकिस्तान रूस के खिलाफ अधिकारहीन हो सकता है लेकिन उसकी संप्रभुता बरकरार है। और देश के उत्तर और पूर्व में रूसी भाषी के प्रभुत्व वाले कज़ाख क्षेत्रों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह कोई ऐसा रुख नहीं अपना रहा है जो रूस के प्रति शत्रुतापूर्ण हो, रूस के लिए असुरक्षा पैदा करे। मेरा हमेशा से यही कहना है कि रूस जैसी शक्ति के साथ आप खुद को सुरक्षित करने के लिए और अधिक असुरक्षा पैदा न करें। कोई भी आपको सुरक्षा देने नहीं आएगा। कोई भी शक्ति संपन्न राष्ट्र इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

हमने देखा है कि उनके पास दो सैन्य अड्डे थे, अमेरिकी। उन्हें जाना पड़ा। और आज, रूस के ज्यादा अड्डे हैं। ये किर्गिस्तान में हैं, ताज़िकिस्तान में तीन अड्डे हैं जो अफगान- ताज़िक सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए, सुरक्षा प्रदाता के रूप में कोई भी रूस की जगह नहीं ले सकता और इन सबके अलावा, यदि आप अपनी गतिविधियों द्वारा पश्चिम से रूस को असुरक्षित महसूस करवाते हैं तो जॉर्जिया, मोल्दोवा और अब यूक्रेन की तरह अपने इलाकों से हाथ धो सकते हैं। इसलिए, विकल्प यही है कि रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखें, न कि नाटो को इस क्षेत्र में लाने के लिए पश्चिमी देशों के बहकावे में आएं। वे यूरोपीय संघ को लेकर इतने चिंतित नहीं होंगे।

वे चिंतित तब होंगे जब इस क्षेत्र में नाटो आ जाएगा। जॉर्जिया को अब नाटो की सदस्यता लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

राजदूत अचल मल्होत्रा

अब्ख़ज़िया पर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। जहाँ तक बात जॉर्जिया की है, उसने अभी तक अब्ख़ज़िया और दक्षिण ओसेतिया पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। लेकिन जहाँ तक रूस का सवाल है, ये दोनों ही स्वतंत्र राष्ट्र हैं, रूस ने इन्हें मान्यता प्रदान की है और कुछ और देशों ने भी, रूस के आदेश पर, इसकी मान्यता स्वीकार कर ली है। इसलिए उन्हें लगता है कि उनके पास इन स्वतंत्र देशों से निपटने का हर वैध कारण है। और जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो जॉर्जिया के पास विरोध करने का कारण होता है। आशा है, लेकिन समय के साथ स्थिति बदलने की संभावना नहीं है।

सवाल मुझसे पूछा गया था, है ना? आपने विकल्पों के बारे में बात की थी, आर्मीनिया के विकल्प के बारे में? अच्छी बात है, इस स्तर पर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आर्मीनिया रूस से निराश है और रूस ने सभी स्वरूपों का नेतृत्व किया है, जो सुरक्षा स्वरूप हैं, विशेष रूप से सीएसटीओ (CSTO)। क्योंकि आर्मीनिया को लगता है कि अज़रबैजान के साथ युद्ध में, 2020 में जब अज़रबैजान ने युद्ध छेड़ा था, वे आर्मीनिया की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए, निश्चित रूप से आर्मीनिया अलग होना चाहता है या कम- से- कम यह सार्वजनिक रूप से रूस के नेतृत्व वाली योजनाओं के प्रति मोहभंग और निराशा व्यक्त कर रहा है।

यह कहाँ- किस दिशा में बढ़ेगा, कहना जल्दबाजी होगी। फ्रांस अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने आर्मीनिया को सैन्य स्तर पर मजबूत बनाने का प्रस्ताव दिया है और फ्रांस में आर्मीनिया के प्रवासियों की बड़ी आबादी भी रहती है। तो, फ्रांस उन देशों में से एक हो सकता है- और परंपरागत रूप से फ्रांस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं।

इसलिए, मैं यह नहीं कहूँगा कि फ्रांस दूसरा विकल्प बन जाएगा। मेरा मतलब है कि यह अपनी घोषित नीति का पालन करने का प्रयास करेगा, जिसके मुताबिक- हमारे पास एक बहु- वेक्टर विदेश नीति है, जिसका अर्थ है कि उस नीति का संक्षेप यह है और या तो नहीं/या, आप समझीं? आप दोस्त बनाना चाहते हैं, इसे और उसे लेकिन न तो इसे न ही उसे। इसलिए,

यह उनकी घोषित नीति है, वे इसका पालन करते हैं या नहीं, हमें देखना होगा। तो इस समय हम इस स्थिति में हैं।

प्रो. संजय पांडेय

यदि मुझे छोटी सी बात जोड़ने की इजाज़त मिले? दक्षिण कौकसस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रूस और पश्चिम, अमेरिका, दोनों समान रूप से शामिल हैं। मध्य एशिया, जहां अमेरिका और पश्चिम के देशों का आना- जाना लगा रहता है, के उलट, चीन और रूस की स्थायी उपस्थिति है। लेकिन दक्षिण कौकसस में, रूस की दिलचस्पी, चाहे वह नागोर्नो- काराब़ाख, दक्षिण ओसेतिया, अब़खज़िया और ऐसे दूसरे क्षेत्र हों, यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप, ओएससीई और फिर शांति साझेदारियां, नाटो, ये सभी दक्षिण कौकसस के देशों से जुड़े रहे हैं। आर्मीनिया, मेरे कहने का मतलब है कि, आर्मीनियाई नरसंहार को मान्यता देने वाले 30 देशों में से अधिकांश यूरोपीय हैं। अज़रबैजान में उनकी दिलचस्पी, अज़रबैजान में निवेश, 30 वर्ष, 1994, रहे हैं। और अपनी तेल पाइपलाइन एवं कनेक्टिविटी संबंधी अन्य परियोजनाओं के कारण जॉर्जिया महत्वपूर्ण है। इसलिए, रूस और यूरोप एवं अमेरिका दोनों इस क्षेत्र में समान रूप संबद्ध हैं। हालाँकि जहाँ तक बात भू- राजनीति और सुरक्षा की है, चीन एक मामूली खिलाड़ी है, हाँ, कनेक्टिविटी की परियोजनाएं में यह जरूर शामिल है।

राजदूत अचल मल्होत्रा

तो, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को, पैनल में शामिल मेरे सहयोगियों को, उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्नों के लिए धन्यवाद कहने का समय आ गया है। मुझे आशा है कि हमारे उत्तर से आपको संतुष्टि मिली होगी। अगर आप चाहें तो जलपान के समय भी हम चर्चा जारी रख सकते हैं।

महानिदेशक महोदया, आपका धन्यवाद। आपकी पहल के लिए बहुत- बहुत धन्यवाद।

कार्यक्रम

भारतीय वैश्विक परिषद

पैनल चर्चा का विषय

दक्षिण कौकसस में बदली स्थितियाँ और उसके प्रभाव

1 मार्च 2024 | 1500 बजे

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

कार्यक्रम *

1500-1510 बजे	**स्वागत भाषण** **राजूदत विजय ठाकुर सिंह** *महानिदेशक, भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली*
1510-1525 बजे	**अध्यक्ष की टिप्पणी** **राजदूत अचल मल्होत्रा** *आर्मीनिया में भारत के पूर्व राजदूत, नई दिल्ली*
1525-1540 बजे	**आख्यान** **प्रोफेसर अजय पटनायक** *पूर्व डीन, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली*
1540-1555 बजे	**आख्यान** **प्रोफेसर संजय के पांडेय** *सेंटर फॉर रशन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली*
1555-1610 बजे	**आख्यान** **प्रोफेसर अख़लाक अहमद** *अध्यक्ष, सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ एसएलएलएंडसीएस, जेएनयू, नई दिल्ली*
1610-1630 बजे	**चर्चा/प्रश्नोत्तर**

** पैनल चर्चा के समन्वय का कार्य आईसीडब्ल्यूए के वरिष्ठ शोध अध्येता डॉ. अतहर ज़फ़ियार द्वारा किया गया था।*

बायो- प्रोफाइल्स

राजदूत अचल मल्होत्रा

राजदूत अचल कुमार मल्होत्रा ने 1981- 2012 तक भारतीय विदेश सेवा में कार्य किया था। ये संयुक्त राष्ट्र और विएना में अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के उप- स्थायी प्रतिनिधि, आर्मीनिया में भारत के राजदूत, जॉर्जिया में भारत के राजदूत रहे हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 2012-14 तक दिल्ली नीति (स्वतंत्र विचार मंच) की अध्यक्षता भी की।

वर्तमान में ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स द्वारा प्रकाशित *इंडियन फॉरेन अफेयर्स* पत्रिका के प्रबंध संपादक हैं। ये तिल्लोतमा फाउंडेशन के प्रतिष्ठित फेलो (दक्षिण कौकसस) हैं।

राजदूत अचल मल्होत्रा ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं: *प्रीहिस्टोरिक माइथोलॉजिकल एंड लीजेंड्री लिंक्स इंडिया : श्रीलंका* (2006); *इंडिया- आर्मीनिया: सो फार येट सो क्लोज भाग 1* (2018) ; *भाग 2* (2023); *द साउथ कौकसस : ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जुगेशन टू इंडिपेंडेंस* (ट्रेसिंग इंडियाज़ फुटप्रिंट्स) (2020).

ये अंतरराष्ट्रीय मामलों के स्वतंत्र विश्लेषक हैं जिन्हें नियमित रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

प्रोफेसर अजय कुमार पटनायक

डॉ. अजय कुमार पटनायक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर और पूर्व डीन थे। ये रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र में दो बार अध्यक्ष रहे हैं। जेएनयू से पीएच.डी. करने वाले प्रोफेसर पटनायक कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, यूके के फैकल्टी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेज़ में विजिटिंग स्कॉलर(1992-93); इंस्टीट्यूट ऑफ एथनोग्राफी, मॉस्को (1999) और इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, मॉस्को (2010), में, आईसीएसएसआर एक्सचेंज स्कॉलर; यदुनंदन सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका (2006) में विजिटिंग सोलंकी प्रोफेसर और स्कॉलर रहे हैं।

प्रो. पटनायक फॉल स्कूल इन रीज़नल स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, गुमीलेव यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी, अस्ताना, कज़ाकिस्तान (सितंबर 2013); अल फ़राबी कजाख़ नेशनल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ (दिसंबर 2010) में; और अल फ़राबी कज़ाख नेशनल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (दिसंबर 2009) में विजिटिंग फैकल्टी भी रहे हैं।

प्रो. अजय पटनायक ने चार पुस्तकें लिखी हैं - *सेंट्रल एशियाः जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी* (रूटलेज़, लंदन/ न्यूयॉर्क, 2016), *नेशंस, माइनॉरिटीज़ एंड स्टेट्स इन सेंट्रल एशिया* (अनामिका, नई दिल्ली, 2003), *सेंट्रल एशियाः बिटवीन मॉर्डेनिटी एंड ट्रेडिशन* (कोणार्क, नई दिल्ली, 1995) और *पेरेस्त्रोइका एंड वूमेन लेबर फोर्स इन सोवियत सेंट्रल एशिया* (न्यू लिटरेचर, नई दिल्ली, 1989)।

प्रो. संजय कुमार पांडेय

प्रो. संजय कुमार पांडेय सेंटर फॉर रशन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जेएनयू, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं। इन्होंने सेंटर के अध्यक्ष और रशन एंड सेंट्रल एशियन एरिया स्टडीज़ प्रोग्राम के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।

ये राजनीति और समाज के साथ- साथ रूस एवं मध्य एशियाई देशों की विदेश नीति पर पाठ पढ़ाते हैं। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के एल.एम. सिंघवी विज़िटिंग फेलो; कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चार्ल्स वेल्स ट्रस्ट विज़िटिंग फेलो; और कैम्ब्रिज सेंट्रल एशिया फोरम, कैम्ब्रिज में विज़िटिंग फेलो रह चुके हैं।

दिसंबर 2014 में ये उज़्बेकिस्तान में संसदीय चुनाव (ओली मजलिस) के लिए और दिसंबर 2007, 2016 और 2021 में उज़्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे।

इनके कुछ हाल में प्रकाशित प्रासंगिक प्रकाशन हैं:

- "रशा- यूक्रेन कॉन्फिलक्ट: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर", *इंडिया टुडे*, फरवरी 25, 2022, *https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/russia-ukraine-confiict-war-news-update-1917690-2022-02-25;*
- इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड एससीओः प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेज इन रीन्यूइंग द संघाई स्पीरिट" (भारतीय वैश्विक परिषद, 2022);
- "रशा एंड यूक्रेन: यूनाइटेड बाई हिस्ट्री डिवाइडेड बाई जीयोपॉलिटिक्स", (सह- लेखक), जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स,संस्करण 12, अंक 1 और 2, पृष्ठ 19 - 28, जनवरी - दिसंबर 2020 (2022 में प्रकाशित);
- "रशा एंड यूक्रेन: शेयर्ड पास्ट, डिफरिंग परसेप्शंस एंड जीयोपॉलिटिक्स", *द वीक,* जनवरी 24, 2022, *https://www.theweek.in/news/world/2022/01/24/russia-and-ukraine-shared-past-difiering-perceptions-and- geopolitics.html*
- "व्हाट लेड टू द प्रोटेस्ट्स इन कज़ाकिस्तान- एंड व्हाट दे मीन फॉर द रीज़न" *द वीक,* जनवरी 14, 2022, *https://www.theweek.in/news/world/2022/01/14/what-led-to-the-protests-in-kazakhstan-and-what-they-mean-fior-the-region.html*

प्रोफेसर अख़लाक अहमद

प्रो. अख़लाक अहमद 'अहान' जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। ये ओरिएंटल इंस्टूट्यूट, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में विज़िटिंग प्रोफेसर भी हैं। इनके विशेषज्ञता क्षेत्रों में हिंद-फ़ारसी अध्ययन, सिल्क रोड क्षेत्र, सूफ़ीवाद, भारतीय ज्ञान परंपरा, अमीर खुसरो, दारा सिकोह, खय्याम, रूमी, बेदिल, आधुनिक फ़ारसी और उर्दू- हिन्दी साहित्य शामिल है।

इन्होंने एएमयू, अलीगढ़; जेएनयू, नई दिल्ली; टीएमयू, तेहरान, ईरान से शिक्षा प्राप्त की है। इनके बीस से भी अधिक पुस्तकों और लगभग सौ शोधपत्रों का प्रकाशन हो चुका है, कई शोध कार्यों का पर्यवेक्षण इन्होंने किया है, सेमिनार आयोजित किए हैं और कई देशों की यात्रा की है। फ़ारसी और उर्दू के कवि हैं और इनकी कविताओं का संग्रह उर्दू भाषा में *सुरूर, ख़राबात, सोचने पर पहरा है*, और फ़ारसी भाषा में *नमाज़ ए इश्क* नाम से प्रकाशित हुए हैं।

इन्हें भारत के राष्ट्रपति ने महर्षि बदरायण व्यास सम्मान *n*-2018; *सादी पुरस्कार* तेहरान- 2021; *उर्दू अकादमी पुरस्कार*, दिल्ली- 2011; *काज़ी अब्दुल- वदूद पुरस्कार, पटना-* 2010; और ईसीओ से अंतरराष्ट्रीय इक़बाल पुरस्कार, तेहरान- 2015 से सम्मानित किया गया है; कई अन्य सम्मानों के अलावा 2017 में ईरान के सर्वोच्च नेताओं, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 2016 और 2018 में भी सम्मानित किया गया था;

और 2019 में उज़्बेकिस्तान के नवाई प्रांत के गवर्नर, अकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर, बाकू- 2017 और अनेकों प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

इनकी कविताओं और अकादमिक योगदान पर केंद्रित करते हुए सहार टीवी, ईरान और डीडी उर्दू द्वारा वृत्तचित्र बनाई गई हैं।

आईसीडब्ल्यूए के बारे में

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच. एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के समूह द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान एवं विचार भंडार के रूप में काम करना था। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ- साथ अतिथि विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान के कार्य करती है। यह नियमित रूप से बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन करता है जिसमें सम्मेलन, सेमिनार, गोलमेज सम्मेलन, व्याख्यान भी शामिल होते हैं। परिषद प्रकाशन कार्य भी करता है। इसके पास समृद्ध पुस्तकालय है, इसकी वेबसाइट सक्रिए रूप से काम करती है और यह ***इंडिया*** नाम की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों में विकास करने हेतु आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ- समूहों और शोध संस्थानों के साथ 50 से अधिक अनुबंध किए हैं।

परिषद की साझेदारी भारत के अग्रणी शोध संस्थानों, विशेषज्ञ समूहों और विश्वविद्यालयों के साथ भी है।

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

www.icwa.in